पेज 08 में...

विधानसभा के विशेष सत्र पर गरमाई सियासत

साप्ताहिक शहर सत्ता

PRGI NO. CTHIN/25/A2378

सोमवार, 27 अप्रैल से 03 मई 2026

हम दिखाएंगे आईना...

पेज 12 में...

नशे का 'नेशनल कॉरिडोर' अब तस्करों के लिए 'डेथ वारंट'

वर्ष : 02 अंक : 08 पृष्ठ : 12 मूल्य : 5 रुपए www.shaharsatta.com

पेज 07 पंजाब ने किया आईपीएल का सबसे बड़ा रन चेज़

संवाद में सिंडिकेट...!

- 30 प्रिंटर्स के होटल सिंडिकेट ने अफसरों की शह पर किया खेल
- मुद्रण सामग्रियों की रेट 'फिक्सिंग' का हुआ सनसनीखेज़ खुलासा
- भनक लगते ही नए CPRO ने टेंडर को हाईजैक होने से पहले किया रद्द
- तीन बार बदली गई तारीख वही टेंडर खुलने के दो घंटे पहले निरस्त

प्रमुख संवाददाता/विकास यादव
मोबाईल नंबर 9425528000

छत्तीसगढ़ संवाद एक बार फिर विवादों के घेरे में है। सुशासन की योजनाओं, नीतियों के विज्ञापन की बंदरबांट के बाद अब करोड़ों रुपये के प्रिंटिंग टेंडर को लेकर "अंदरूनी खेल" का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जिस दिन प्रिंटर्स का टेंडर खुलना था, ठीक उसी दिन शासन ने इसे बिना पुख्ता कारण बताये निरस्त कर दिया। वजह जानकर आप हैरान रह जाएंगे, खबर है कि रायपुर के प्रिंटर्स ने एक बड़ा 'सिंडिकेट' बनाकर टेंडर को हाईजैक करने की कोशिश की थी, जिसकी शिकायत शासन तक पहुंची तब संवाद ने आनन-फानन में जिस टेंडर की नियत तिथि तीन बार बढ़ाई थी उसे टेंडर खुलने के दो घंटे पहले निरस्त कर दिया। अकेले समग्र शिक्षा की किताबों की छपाई का टेंडर निकला था। ऐसे सभी शासकीय विभागों के लिए पोस्टर-पाम्पलेट, बुकलेट, मैगजीन, काफी टेबल बुक कार्ड आदि का मुद्रण टेंडर करोड़ों रूपये खर्च कर किया जाता है।

शहर सत्ता/रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के मुद्रण कार्यों का 'नोडल' कहा जाने वाला छत्तीसगढ़ संवाद एक बार फिर बड़े घोटाले की सुगबुगाहट से हिल गया है। सरकारी टेंडर को अपनी मुट्ठी में करने के लिए रायपुर के 30 प्रिंटर्स ने मिलकर एक ऐसा 'सिंडिकेट' तैयार किया, जिसने न केवल शासन की पारदर्शिता को चुनौती दी, बल्कि करोड़ों रुपये के कामों को आपस में बंदरबांट करने की पूरी पटकथा लिख दी। लेकिन, सिंडिकेट के भीतर मचे घमासान और शासन की सख्ती ने इस 'फिक्सिंग' के खेल को ऐन वक्त पर बिगाड़ दिया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को शिकायत की गई थी। मामले की भनक लगते ही नए आयुक्त जनसंपर्क रजत बंसल ने फौरी कार्रवाई करते हुए टेंडर रिफॉर्म किया बलकि इसमें शामिल संवाद के लोगों का भी प्रभार बदल दिया। ना खाऊंगा और ना ही खाने दुंगा की तर्ज पर सीपीआरओ श्री बंसल ने सख्त रव्वैया अख्तियार कर लिया है। जल्द ही संवाद में लंबे समय से जमे अधिकारीयों का भी प्रभार बदलेगा।

इसी होटल में हुई थी मीटिंग

QUALITY OFFSET

होटल में सजी 'फिक्सिंग' की महफिल

इस पूरे खेल की पटकथा रायपुर के नामी होटलों में लिखी गई। 20 से 25 हजार अलग-अलग सामग्रियों की प्रिंटिंग का रेट तय करना कोई आसान काम नहीं था, इसलिए सींडीकेट के 30 प्रिंटर्स का एक समूह एकजुट हुआ।

पहली बैठक: 22 मार्च को रायपुर के 'इंडियन हेरिटेज' होटल में हुई, जहां चारों कैटेगरी के प्रिंटिंग काम को करने के लिए सिंडिकेट बनाने और टेंडर हासिल करने की रणनीति बनी।

दूसरी बैठक: 28 मार्च को उसी होटल में हुई, जिसमें 5 प्रमुख फर्मों (महावीर ऑफसेट, अरिहंत ऑफसेट, मां दुर्गा प्रिंटर्स, डिजिटल टेक्नोलॉजी कंकालीपारा और प्रिंटेक स्केनर प्रिंटर्स) को रेट लिस्ट और काम की लिस्टिंग का जिम्मा सौंपा गया।

फाइनल स्ट्राइक : 3 अप्रैल से 8 अप्रैल तक रायपुरा के होटल स्प्रिंट टी में पूरा सिंडिकेट जमा हुआ। यहां होटल बुक कर बाकायदा ऑनलाइन फार्म भरे गए और हजारों सामग्रियों के रेट 'आपसी तालमेल' से तय किए गए।

क्या है पूरा मामला?

टेंडर का उद्देश्य : छत्तीसगढ़ संवाद ने राज्य के सभी विभागों की करीब 25,000 मुद्रण सामग्रियों (जैसे पोस्टर, पांपलेट, कैलेंडर, फॉर्म, रजिस्टर, बुकलेट आदि) की प्रिंटिंग के लिए योग्य फर्मों के इम्पैनलमेंट हेतु 28 जनवरी 2026 को निविदा (क्रमांक 4663) जारी की थी।

सिंडिकेट की साजिश : प्रतियोगिता को खत्म करने के लिए रायपुर के 30 प्रिंटर्स एकजुट हुए और एक 'सिंडिकेट' बनाया। इनका मकसद आपसी तालमेल से रेट तय करना था ताकि काम इन्हीं के बीच रहे और कोई बाहरी प्रिंटर एंट्री न कर सके।

होटल में फिक्सिंग : इस सिंडिकेट ने शहर के होटलों में गुप्त बैठकें कीं। 3 से 8 अप्रैल तक होटल स्प्रिंट टी रायपुरा में बाकायदा 'वार रूम' बनाकर 25 हजार आइटम्स के रेट लिस्ट तैयार किए गए और वहीं से ऑनलाइन फॉर्म भरे गए।

बगावत का कारण : सिंडिकेट के आकाओं ने '19 बनाम 11' का फॉर्मूला बनाया। यानी 19 पुराने प्रिंटर्स को ही काम दिलाने के लिए कम रेट डलवाए गए और बाकी 11 को 'सपोर्ट' करने के नाम पर अधिक रेट भरने को कहा गया।

नतीजा: WhatsApp ग्रुप पर प्रिंटर्स के बीच हुए विवाद और भेदभाव की खबर शासन तक पहुंच गई। गड़बड़ी की पुख्ता जानकारी मिलते ही शासन ने टेंडर खुलने वाले दिन ही पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया।

"टेंडर में गड़बड़ी हो रही है इसकी शिकायत हमें इंटर्नलि मिली थी जिसके बाद इस पूरे प्रक्रिया को निरस्त किया गया है, पुन: इसकी प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस मामले में कुछ का प्रभार भी बदला गया है।"

रजत बंसल, आयुक्त जनसंपर्क छ.ग.शासन

व्हाट्सअप ग्रुप में हाईजेकर्स की चैटिंग

"शहर सत्ता" के पास सिंडिकेट का व्हाट्सअप ग्रुप की वीडियो और फूटेज हाथ लगे हैं, जिसमें टेंडर लेने होने वाली बैठकों और बैठक में शामिल होने वाले लोगों के चैटिंग तथा सिंडिकेट में शामिल लोगों से होटल में होने वाले खर्चे और उसके रकम के लिए चंदा करने पैसे देने के स्क्रीन शाट शामिल हैं।

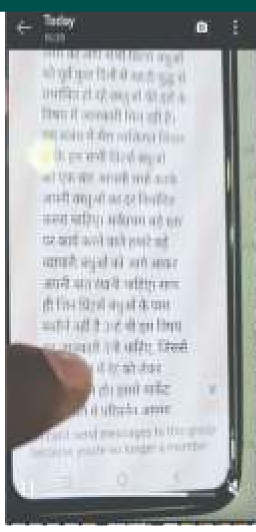
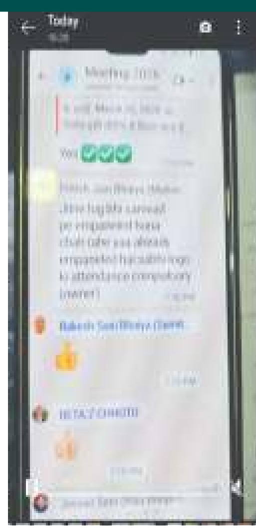

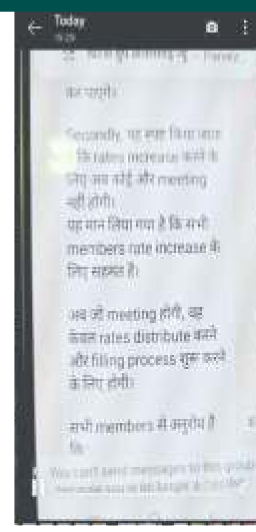

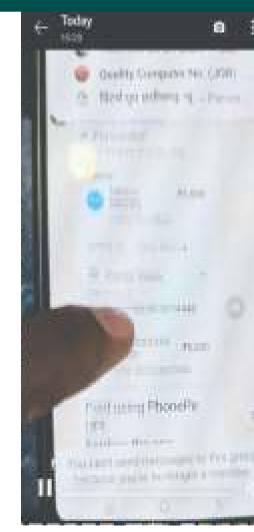

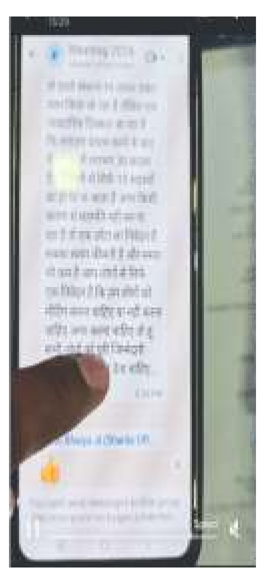

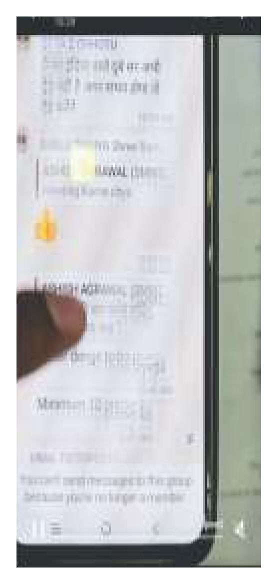

होटल खर्च भी वसूली से

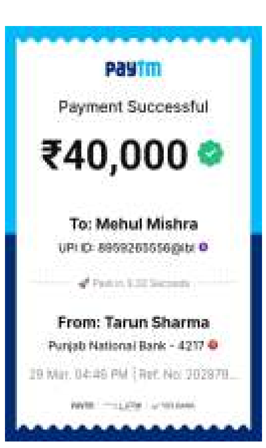

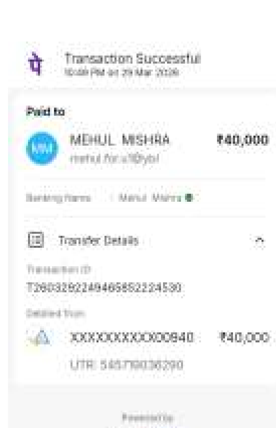

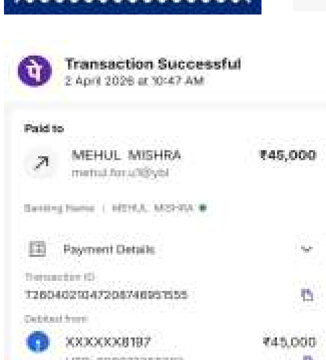

होटल के खर्च के लिए पुराने 19 प्रिंटर्स से (जिन्हें टेंडर मिलना था) उनसे 40-40 हजार रुपये और नए 11 प्रिंटर्स (जिन्हें टेंडर में सपोर्ट करना था) उनसे 20 हजार रुपये वसूल गए थे। वसूले गए राशि का उपयोग हॉटल के किराया, खाना, चाय नास्ता और दारू में हुआ है। जिन प्रिंटरों का नाम टेंडर में आता वो अपनी मर्जी से उन 11 प्रिंटरों को काम सौंपते जो टेंडर लेने में सपोर्ट करते, लेकिन कई प्रिंटरों को यह बात नागवार गुजरी जिसके कारण इस मामले की गुपचुप तरीके से शासन और विभागीयस्तर पर शिकायत हुई।

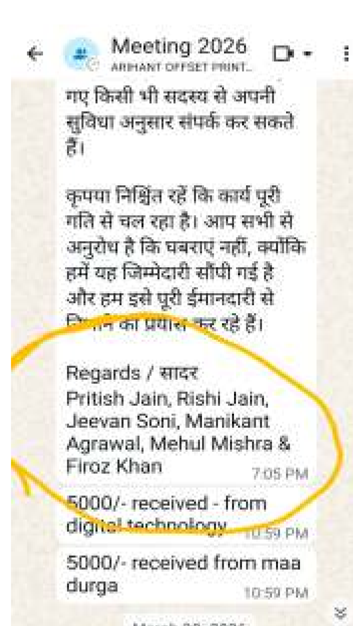

बिना कारण बताए टेंडर निरस्त, प्रिंटर्स में हड़कंप

पहले टेंडर जमा करने की तारीख 27 मार्च थी, जिसे प्रिंटर्स की मांग पर बढ़ाकर 13 अप्रैल किया गया था। जैसे ही सभी ने टेंडर जमा किए, संवाद की वेबसाइट पर आदेश क्रमांक 130 चमकने लगा, जिसमें बिना कोई कारण बताए पूरी प्रक्रिया निरस्त कर दी गई। सिंडिकेट बनाने वाले प्रिंटर्स अब जवाब मांग रहे हैं, लेकिन शासन की चुप्पी इशारा कर रही है कि "दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है।"

सुलगते सवाल

- क्या छत्तीसगढ़ संवाद के अधिकारियों को इस सिंडिकेट की भनक पहले से थी?
- एक ही होटल में बैठकर 30 लोग ऑनलाइन फॉर्म भर रहे थे, क्या यह साइबर सुरक्षा और निष्पक्ष टेंडर प्रक्रिया का उल्लंघन नहीं है?
- क्या अब उन प्रिंटर्स पर ब्लैकलिस्ट एवं अमानत राशि राजसात करने की कार्रवाई होगी जिन्होंने सिंडिकेट बनाकर प्रतिस्पर्धा को खत्म करने की कोशिश की?

किस कैटेगरी में कौन से काम

- **ए कैटेगरी (मल्टी कलर) :** पोस्टर-पाम्पलेट, बुकलेट, मैगजीन, काफी टेबल बुक आदि।
- **बी कैटेगरी (सिंगल कलर) :** उत्तर पुस्तिका, रजिस्टर तथा अन्य सभी ब्लैक एंड व्हाईट कलर वाले सभी मुद्रण कार्य।
- **सी कैटेगरी (स्क्रीन प्रिंटिंग) :** आमंत्रण-पत्र, लिफाफा, सभी शासकीय पास जैसे मुद्रण कार्य।
- **डी कैटेगरी (वेब आफसेट) :** बुलेटीन्स, गजट, कम पेज वाले मैगजीन जैसे कार्य।

राज्य सरकार ने लगातार मुद्रण कार्यों में घोटालों के बाद एक आदेश जारी किया जिसके अनुसार सभी प्रचार-प्रसार एवं विभागों के मुद्रण कार्य संबंधित सभी काम छत्तीसगढ़ संवाद के माध्यम से ही कराने हैं, इसी आदेश के बाद अन्य घोटालों में लिप्त प्रिंटरों का सिंडिकेट संवाद में हावी हो गए हैं।

भूमि पूजन की तैयारी के बाद पता चला जमीन निगम की नहीं

मामला जोन-3 कमिश्नरी में खम्हारडीह पानी टंकी बनाने का

रायपुर। नगर निगम जोन-3 कमिश्नरी अंतर्गत नेताजी सुभाषचंद्र बोस वार्ड के पेयजल समस्याग्रस्त खम्हारडीह एरिया में 22 करोड़ रुपये की लागत से जहां टंकी बननी थी, वह जमीन महिला बाल विकास विभाग की निकल गई। इसके चलते यहां 21 अप्रैल को नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव के हाथों होने वाले भूमिपूजन कार्यक्रम को लेकर नगर निगम का अमला असमंजस की स्थिति में आ गया है। 25 लाख लीटर की क्षमता वाली इस टंकी के बनने से आने वाले साल में खम्हारडीह रेलवे पटरी के आसपास के पूरे एरिया में रहने वाली लगभग 5 हजार की आबादी को इससे राहत मिल जाती, लेकिन ऐनवक्त पर यहां निगम की जमीन नहीं होने के कारण यह योजना भी खटाई में पड़ रही है।

अधिकारियों ने बताया कि यहीं टंकी बनाने के लिए कम से कम 15 हजार वर्गफीट जमीन निगम को चाहिए, जो नहीं मिल पाई। 21 अप्रैल को इसी एरिया के नागरिक दोपहर को घंटों खड़े रहकर टैंकर का इंतजार करते देखे गये। यहां टैंकर के आते ही पाइपलाइन डालकर मुंह से पानी खींचकर अपने-अपने बर्तन भरने के चक्कर में अब यहां विवाद के साथ ही मारपीट की भी नौबत आने लगी है। इस वार्ड में दूसरी बार भाजपा के रोहित साहू के बाद उनकी पत्नी पुष्पा साहू चुनाव जीतकर आई हैं। पिछले साल से ही इस वार्ड में पानी की समस्या विकराल रूप ले चुकी थी, इसका समाधान इस साल भी नहीं हो पाया।

महादेवघाट प्रोजेक्ट कोर्ट में चला गया

महादेवघाट प्रोजेक्ट की स्वीकृति अक्टूबर 2025 में ही मिल गई थी। 1886.19 लाख के इस प्रोजेक्ट के लिए नवंबर में टेंडर जारी किया गया। अभी पिछले महीने मार्च में इसका टेंडर खुला, इसमें निविदा दर अधिक होने के कारण शासन ने इसमें आपत्ति दर्ज करा दी। इसके कारण टेंडर जिसके नाम से खुला वह अब कोर्ट में वाद दायर कर दिया है।

जमीन विवाद के कारण छुइया तालाब काम रुका

अधोसंरचना बजट अंतर्गत नगर निगम छुइया तालाब सौंदर्यीकरण के लिए 296.28 लाख रुपये का टेंडर किया था। इस काम के लिए 20 अक्टूबर 2025 को वर्कऑर्डर जारी किया गया था। लेकिन यहां भी सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं होने के कारण अब वर्कऑर्डर के बाद टेंडर निरस्तीकरण की प्रक्रिया नगर निगम शुरू कर रहा है।

भीषण गर्मी से हलाकान लगातार बढ़ रहा पारा

रायपुर। राजधानीवासी शुक्रवार को भीषण गर्मी से हलाकान रहे। दिनभर ग्रीष्म लहर जैसे हालात रहे। वहीं शाम-रात में भी गर्म हवाएं चलती रही। मौसम विभाग ने रायपुर समेत मध्य छत्तीसगढ़ के एक-दो स्थानों में 25 अप्रैल से 27 अप्रैल तक ग्रीष्म लहर चलने की चेतावनी दी है। प्रदेश में सर्वाधिक अधिकतम तापमान राजनांदगांव में 44.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। रायपुर में अधिकतम तापमान 43.4 डिग्री सेल्सियस रहा। शनिवार को रायपुर में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणिका पूर्वी उत्तर प्रदेश से दक्षिण बांग्लादेश तक बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल होते हुए 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। दूसरा द्रोणिका / हवा की अनियमित गति पूर्वी विदर्भ से कोमोरिन क्षेत्र तक तेलंगाना, अंदरूनी कर्नाटक और तमिलनाडु होते हुए 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। एक चक्रवात महाराष्ट्र और उसके आसपास 3.1 किलोमीटर से 5.8 किलोमीटर ऊंचाई तक विस्तारित है। 25 अप्रैल को प्रदेश के मध्य भाग में ग्रीष्म लहर जैसे स्थिति बने रहने की संभावना है। वहीं, 26 अप्रैल से दक्षिण बस्तर के जिलों में गर्मी से राहत रहने की संभावना बन रही है। प्रदेश में भीषण गर्मी पड़ी जगदलपुर को छोड़कर प्रदेश के अधिकांश भागों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहा।

सट्टेबाज के घर से करोड़ों की प्रॉपर्टी-कारों के पेपर जब्त

- पुलिस ने कोर्ट की अनुमति लेकर बाबू खेमानी के घर की जांच-पड़ताल की

रायपुर। तीन राज्यों में कंट्रोल रूम खोलकर देश भर में ऑनलाइन क्रिकेट सट्टेबाजी कराने के आरोप में अपने 26 साथियों-कर्मियों के गिरफ्तार बाबू उर्फ गुलशन खेमानी से पूछताछ के बाद अब पुलिस ने उसके घर समेत अन्य ठिकानों पर छापेमारी की है। सर्च वारंट लेकर महिला स्टाफ के साथ आरोपी के टाटीबंध मारुति इन्क्लेव स्थित मकान में पहुंची पुलिस टीम ने करीब तीन घंटे तक जांच-पड़ताल की। इस दौरान मकान, दुकान, प्लॉट, कृषि भूमि और वाहनों के ढेरों दस्तावेज जब्त किए गए हैं। करीब एक दर्जन बैंक एकाउंट की जानकारी भी मिली है, जिन्हें सीज कराया जा रहा है। इधर बाबू खेमानी की गिरफ्तारी के एक हफ्ते बाद पुलिस के सर्च से यह सवाल उठ रहे हैं कि मकान में जांच कार्रवाई के लिए इतना इंतजार क्यों किया गया। जबकि रायपुर में ही कई ऐसे उदाहरण हैं जब आरोपी की गिरफ्तारी के तुरंत बाद पुलिस ने घर में छापेमारी करके जांच-पड़ताल की है। उल्लेखनीय है कि बाबू खेमानी इस वक्त जेल में है। पुलिस ने रिमांड पर लेकर पांच दिनों तक कड़ी पूछताछ की है। आरोपी डायमंड सट्टा एप को खरीदकर अलग-अलग नामों से उसके ही लिंक व पैनल बेचकर सट्टेबाजी तो कराता ही था। खुद भी अपने रिश्तेदारों और करीबी लोगों के साथ मिलकर कई राज्यों में ऑनलाइन सट्टेबाजी का नेटवर्क खड़ा कर लिया है। दुबई समेत कई देशों में उसके संपर्क की जांच पुलिस कर रही है। पूछताछ और जांच में कई रिश्तेदारों के सट्टेबाजी में शामिल होने के सबूत मिले हैं।

ऑपरेशन कालचक्र 0.2: एक ही रात दबोचे गए 196 वारंटी

रायपुर। पुलिस कमिश्नरी की तरफ से चला जा रहे सर्च ऑपरेशन कालचक्र 0.2 के तहत पुलिस ने गुरुवार-शुक्रवार की रात नॉर्थ जोन कमिश्नरेट के पांच थाना क्षेत्रों में व्यापक छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे अपराधियों, वारंटियों के घरों में दबिश देकर 196 वारंटियों को दबोचा, जिनमें 45 स्थायी वारंटी, 59 गिरफ्तारी वारंटी और 92 जमानती वारंटी शामिल हैं। उपायुक्त मयंक गुर्जर के नेतृत्व में चलाए गए इस ऑपरेशन में विशेष टीमों ने गुढ़ियारी, पंडरी, खमतराई, उरला और खम्हारडीह थाना क्षेत्रों में दबिश दी। अभियान के दौरान उरला पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। उरला-बेंद्री रोड पर घेराबंदी कर एक मारुति स्विफ्ट कार (सीजी 04 क्यूडब्ल्यू 2173) की तलाशी ली गई, जिसमें लगभग 60-70 किलोग्राम चोरी का कॉपर कॉइल बरामद हुआ। तीन आरोपियों राजकुमार कुशवाहा सोंडोंगरी कबीरनगर, हरिओम शाह मजदूर नगर सरोरा और करण साहू हीरापुर कबीरनगर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा चाकू लेकर घूम रहे आरोपी रामेश्वर यादव सरोराबाजार उरला समेत 3 को गिरफ्तार किया है।

एक दिन पहले दबोचे गए थे 53

एक दिन पहले ही मध्य जोन कमिश्नरी में अपराधियों और असामाजिक तत्वों के हौसले पस्त करने 'कॉम्बिंग गश्त' ऑपरेशन चलाया। आईपीएस उमेश प्रसाद गुप्ता (डीसीपी सेंट्रल जोन) के नेतृत्व में एडिशनल डीसीपी तारकेश्वर पटेल, एसीपी रमाकांत साहू एवं दीपक मिश्रा के साथ 150 से अधिक जवानों ने सात थाना क्षेत्रों में 20 वारंटियों समेत 53 संदेही-आरोपियों को दबोचा था।

सीजी पीएससी लेगा परीक्षा लेकिन 'अग्निवीर आरक्षण' बना पेंच

जेल विभाग में होगी 100 प्रहरियों की भर्ती

रायपुर। छत्तीसगढ़ के जेल विभाग में 11 साल बाद राज्य शासन ने जेल प्रहरियों के रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने को हरी झंडी दे दी है। 100 प्रहरियों के पदों पर भर्ती को मंजूरी मिली है, जो जरूरत पदों का सिर्फ 20 फीसदी हिस्सा है। इस भर्ती को लेकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजी पीएससी) ने परीक्षा आयोजित करने की सैद्धांतिक सहमति दे दी है। व्यापम ने 2026 में पूरे साल खुद को बताया व्यस्त : शुरुआत में इस भर्ती परीक्षा का प्रस्ताव छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल (व्यापम) को भेजा गया था। हालांकि, व्यापम ने वर्ष 2026 के अपने व्यस्त कैलेंडर और समय के अभाव का हवाला देते हुए इनकार कर दिया। इसके बाद जेल विभाग ने लोक सेवा आयोग से संपर्क किया, जहां से सकारात्मक संकेत मिले हैं। हालांकि, अभी तक आवेदन की तिथि और परीक्षा के महीने को लेकर आधिकारिक घोषणा होना बाकी है।

15 साल पहले 535 पद थे रिक्त फिर भी केवल 100 मंजूर

सूत्रों के मुताबिक जेल विभाग में स्टाफ की भारी कमी है। 15 साल पहले स्वीकृति के अनुपात में ही 535 पद रिक्त हैं। कायदे से स्वीकृत पद को भरने के साथ ही

2026 में कैदियों की क्षमता के आधार पर और अतिरिक्त पद मंजूर किए जाने थे। लेकिन फिलहाल केवल 100 पदों पर ही भर्ती की मंजूरी दी है। यह कुल रिक्तियों का मात्र 20 प्रतिशत है। गौरतलब है कि इससे पहले वर्ष 2014 में प्रहरियों की भर्ती की गई थी। 11 साल बाद शुरू हुई इस प्रक्रिया में भी कम पदों की मंजूरी से युवा बेरोजगारों के हित प्रभावित हो रहे हैं।

अग्निवीर आरक्षण के कारण परीक्षा विलंबित होने के संकेत

भर्ती प्रक्रिया में देरी का एक बड़ा तकनीकी कारण 'अग्निवीर जवानों' को मिलने वाला आरक्षण है। शासन की घोषणा के अनुसार, पुलिस और जेल जैसी भर्तियों में अग्निवीरों को 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना है। लेकिन इस आरक्षण को लागू करने के लिए अभी तक सेवा नियमों में आवश्यक संशोधन कर नए नियम नहीं बन पाए हैं। जानकारों का मानना है कि जब तक यह नियमावली स्पष्ट नहीं होती, विज्ञापन जारी होने में विलंब हो सकता है।

जेलों की स्थिति: क्षमता से अधिक कैदी, स्टाफ की कमी

प्रदेश की जेलों में स्टाफ की कमी के कारण सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जेलों में कैदियों को रखने की कुल क्षमता 15,000 है, जबकि वर्तमान में लगभग 21,000 कैदी हैं। इतने ज्यादा बंदियों की निगरानी और सुरक्षा के लिए केवल 1,500 स्टाफ तैनात है। कायदे से यह संख्या 15 साल पहले के मानकों के अनुसार भी 2,000 से अधिक होनी चाहिए। कैदियों की बढ़ती संख्या और स्टाफ की कमी ने जेलों की सुरक्षा को खतरे में डाल दिया है।

छत्तीसगढ़ विधानसभा में 25 साल में 15 सौ घंटे से ज्यादा बजट चर्चा

25 साल में आयोजित हुए 75 सत्र, कई छोटी विधानसभाओं से ज्यादा चर्चा

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा ने हाल ही में अपना रजत जयंती वर्ष मनाया है। इन 25 वर्षों के सफर में विधानसभा ने अपनी अलग पहचान बनाई है। गर्भगृह में जाने पर सदस्यों के स्वयं निलंबन के नियम के कारण देशभर में छत्तीसगढ़ विधानसभा की चर्चा तो है ही, अब बजट चर्चा के मामले में भी छत्तीसगढ़ विधानसभा कई छोटी विधानसभाओं से आगे है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 25 बरसों में आम बजट और पूरक बजट पर 1527 घंटे से ज्यादा चर्चा हुई है, यह 63 दिन के बराबर है। राज्य स्थापना के बाद पहले सत्र से लेकर दिसम्बर में आयोजित पिछले सत्र तक यानी 25 बरसों में छत्तीसगढ़ विधानसभा के 75 सत्र आयोजित हो चुके हैं। इन सत्रों के दौरान सरकार द्वारा पेश आम एवं पूरक बजटों पर विस्तार से चर्चा हुई है। ज्यादातर छोटी विधानसभाओं में कम चर्चा के बाद ही बजट पारित कर दिए जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ विधानसभा में विभागवार मांगों के बाद ही बजट पारित किए गए हैं। हर सत्र में पेश होने वाले पूरक बजट पर भी 3-4 घंटे से कम चर्चा कभी नहीं हुई।

विधानसभासत्र	चर्चा	घंटे
प्रथम विधानसभा	8 सत्र	126.63 घंटे
द्वितीय विधानसभा	14 सत्र	340.57 घंटे
तृतीय विधानसभा	13 सत्र	351.34 घंटे
चतुर्थ विधानसभा	17 सत्र	364.04 घंटे
पंचम विधानसभा	17 सत्र	202.80 घंटे
षष्ठम विधानसभा	6 सत्र	141.67 घंटे

डॉ. रमन के सीएम-वित्त मंत्री रहने के दौरान ज्यादा चर्चा

राज्य में द्वितीय से लेकर चतुर्थ विधानसभा के दौरान बजट पर ज्यादा चर्चा हुई है। द्वितीय से लेकर चतुर्थ विधानसभा के दौरान डॉ. रमन सिंह मुख्यमंत्री के साथ-साथ वित्त मंत्री भी रहे। इन्हीं तीनों विधानसभाओं में ही बजट पर ज्यादा चर्चा हुई। तीनों कार्यकाल में सदन में एक हजार घंटे से ज्यादा चर्चा हुई। प्रथम विधानसभा के 3 साल में बजट पर सबसे कम सिर्फ 126 घंटे ही चर्चा हो पाई थी।

सिर्फ एक बार गिलोटिन से बजट पारित

छत्तीसगढ़ विधानसभा के इतिहास में सिर्फ एक बार ही गिलोटिन से बजट पास करने की नौबत आई थी। पंचम विधानसभा में मार्च 2020 के बजट सत्र में कोरोना संक्रमण के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के कारण बिना चर्चा के ही बजट पारित किया गया था। वैसे पंचम विधानसभा के पांच वर्षों में ही सबसे कम सिर्फ 202.80 घंटे ही चर्चा ही हुई थी।

25 बरसों में 4 हजार घंटे कुल चर्चा

प्रथम से लेकर षष्ठम विधानसभा तक 25 बरसों में बैठकों में कुल करीब 4 हजार घंटे की चर्चा हुई। यह भी छोटी विधानसभा की तुलना में काफी ज्यादा है। इसमें भी सबसे ज्यादा 933 घंटे की चर्चा द्वितीय विधानसभा में हुई थी, जबकि तृतीय और चतुर्थ विधानसभाओं में बैठकों पर क्रमशः 836 और 845 घंटे चर्चा कार्यसूची के सभी विषयों पर हुई। प्रथम विधानसभा के 3 वर्षों में करीब 538 घंटे चर्चा हुई थी।

ईडी का बड़ा खुलासा: छत्तीसगढ़ में नक्सलियों को फंडिंग की आशंका

रायपुर। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शुक्रवार को एक बड़ा खुलासा किया है। ईडी ने बताया कि फेमा (फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट) के तहत गत 18 और 19 अप्रैल को चलाए गए तलाशी अभियान में विदेशी डेबिट कार्ड्स से धमतरी व बस्तर में साढ़े छह करोड़ रुपए निकाले गए हैं, जिसे ईडी ने संदिग्ध व असामान्य माना है। ईडी ने आशंका जताई है कि इस राशि की फंडिंग वामपंथी उग्रवाद (नक्सलियों) की मदद के तौर की जा सकती है।

- विदेशी डेबिट कार्ड्स से धमतरी व बस्तर में निकाले गए साढ़े छह करोड़ रुपए

ईडी ने फेमा के तहत चलाया तलाशी अभियान ईडी ने इस समानांतर कैश-आधारित अर्थव्यवस्था को देश की सुरक्षा और वित्तीय अखंडता के लिए एक गंभीर खतरा करार दिया है और गैर-कानूनी गतिविधियों के लिए अवैध फंड्स के लेन-देन को बढ़ावा देने के रूप में देख रही है। ईडी दिल्ली कार्यालय ने अधिकृत बयान में बताया कि फेमा के तहत चलाए गए तलाशी अभियान में कई राज्यों के छह स्थानों की तलाशी ली गई। इस तलाशी अभियान में विदेशी बैंक डेबिट कार्ड्स का इस्तेमाल करके, रेगुलेटरी चैनलों को दरकिनार करते हुए, फंड्स की संदिग्ध निकासी और इस्तेमाल की जानकारी सामने आई है। यह इन्वेस्टिगेशन भारत में 'टिमोथी इनिशिएटिव' (टीटीआई) के नाम से जाने जाने वाले एक आंदोलन और उससे जुड़े लोगों की गतिविधियों से संबंधित है।

राज्य में पेट्रोल 22 दिन व डीजल 15 दिन का स्टॉक

रायपुर। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में लगभग 77,111 किलोलीटर पेट्रोल उपलब्ध है, जो लगभग 22 दिनों की आवश्यकता के बराबर है। 84,295 किलोलीटर डीजल उपलब्ध है। यह करीब 15 दिनों की खपत के लिए पर्याप्त है। राज्य सरकार ने आश्वस्त किया है कि प्रदेश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है तथा आपूर्ति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है। खाद्य विभाग ने कहा है कि प्रदेश में पेट्रोल व डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध होने के साथ ही आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है। किसी प्रकार की कमी की स्थिति नहीं है। नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। प्रदेश में संचालित 2516 पेट्रोल पंपों तथा तीनों प्रमुख ऑयल कंपनियों के डिपो में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल व डीजल उपलब्ध है। मार्च 2026 में प्रदेश की मासिक पेट्रोल आवश्यकता 1.01 लाख किलोलीटर के विरुद्ध 1.27 लाख किलोलीटर (126 प्रतिशत) की आपूर्ति की गई। वहीं, अप्रैल 2026 में 23 अप्रैल तक 1.60 लाख किलोलीटर पेट्रोल प्राप्त हो चुका है। इसी प्रकार मार्च में डीजल की आवश्यकता 1.64 लाख किलोलीटर के मुकाबले 3.00 लाख किलोलीटर (183 प्रतिशत) आपूर्ति हुई, जबकि अप्रैल 2026 में 23 अप्रैल तक 1.38 लाख किलोलीटर डीजल की आपूर्ति हो चुकी है।

मनमानी फीस नहीं बढ़ाएं स्कूल, विशेष दुकान से बुक-ड्रेस खरीदने बाध्य न करें

- पालकों की शिकायत के बाद मुख्य सचिव ने दिए कलेक्टरों-डीईओ को कड़े निर्देश

रायपुर। फीस बढ़ाने, किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने में निजी स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। पालकों की शिकायत को मुख्य सचिव ने गंभीरता से लेते हुए सभी जिलों के कलेक्टरों एवं जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को निर्देशित किया है कि सभी स्कूलों में फीस विनियमन समिति को सक्रिय किया जाए और नियम विरुद्ध फीस वृद्धि करने वाले निजी स्कूलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। साथ ही कहा है कि कलेक्टर सुनिश्चित करें कि निजी स्कूल पालकों को दुकान विशेष से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए बाध्य न करें।

प्रदेश में छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक 2020 लागू है। इसमें स्पष्ट प्रावधान है कि प्रत्येक निजी स्कूलों में विद्यालय फीस समिति का गठन किया जाना है। यह समिति प्रतिवर्ष पूर्व वर्ष की फीस में अधिकतम 8 फीसदी की सीमा में बढ़ोत्तरी का अनुमोदन कर सकेगी। इससे ज्यादा फीस बढ़ाने की स्थिति में जिला फीस समिति से अनुमोदन कराना आवश्यक है। अधिनियम लागू होने के एक-दो साल तक तो नियमों का पालन किया गया परंतु अब स्कूलों में फीस समिति के नाम पर खानापूर्ति की गई है। वहीं जिला एवं राज्य स्तरीय फीस समिति का अता-पता नहीं है। जिला स्तरीय समिति की बैठक कब हुई और क्या निर्णय हुए, किसी को खबर ही नहीं होती। जिसको लेकर पालक सवाल उठा रहे हैं। इधर, शासन-प्रशासन का लगाम नहीं होने के कारण निजी स्कूलों ने फिर से मनमाने तरीके से फीस बढ़ाना शुरू कर दिया है। कई स्कूलों ने 10 से 12 फीसदी तक फीस बढ़ाई है जबकि स्कूल 8 फीसदी से अधिक की फीस अपने स्तर पर नहीं बढ़ा सकते।

निजी प्रकाशकों की किताबें खरीदने नहीं करेंगे बाध्य

शासन ने फीस के अलावा निजी स्कूलों द्वारा एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबों के बजाय निजी प्रकाशकों की किताबें खरीदने के लिए बाध्य किए जाने पर भी कड़ा रुख अपनाया है। मुख्य सचिव ने कहा है कि सीजी बोर्ड से संबद्धता प्राप्त निजी स्कूलों में कक्षा 1 से 10 तक एससीईआरटी की किताबें पापुनि के माध्यम से निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। ऐसे में विद्यार्थियों-पालकों को किसी अन्य प्रकाशकों की किताबें खरीदने के लिए बाध्य नहीं किया जाए।

पानी दोहन को लेकर रायपुर क्रिकेट स्टेडियम को एनजीटी का नोटिस

देश के 6 प्रमुख स्टेडियमों को कारण बताओ नोटिस

रायपुर। राजधानी रायपुर के क्रिकेट प्रेमियों और खेल जगत के लिए एक चिंताजनक खबर सामने आई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने जल संरक्षण के नियमों का उल्लंघन करने और आवश्यक जानकारी साझा न करने के कारण रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम सहित देश के 6 प्रमुख स्टेडियमों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एनजीटी ने इन स्टेडियमों से पूछा है कि निर्देशों का पालन न करने पर उनके संचालन को सस्पेंड (निलंबित) क्यों न कर दिया जाए? यह पूरा मामला क्रिकेट मैदानों के रखरखाव के लिए भूजल के अत्यधिक दोहन से जुड़ा है। एनजीटी में 2021 में एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि व्यावसायिक और मनोरंजन के उद्देश्यों के लिए आयोजित क्रिकेट मैचों में जल संरक्षण की अनदेखी की जा रही है।

ऐसे में क्या हो पाएगा क्रिकेट मैच?

जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कड़ा रुख अपनाया है। आवेदक के वकील ने एनजीटी से मांग की है कि जब तक ये स्टेडियम नियमों का पालन नहीं करते, तब तक यहां सभी खेल गतिविधियों को पूरी तरह से बंद कर देना चाहिए।

रायपुर समेत इन शहरों के स्टेडियमों को भी नोटिस

- शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम, रायपुर
- अरुण जेटली स्टेडियम, दिल्ली
- सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर
- डीवाई पाटिल स्टेडियम, मुंबई
- इकाना क्रिकेट स्टेडियम, लखनऊ
- बाराबती स्टेडियम, कटक

संपादकीय

● सुकांत राजपूत

झाड़ू से 'आप' सफाई

आम आदमी पार्टी (आप) का वर्तमान संकट केवल कुछ नेताओं के जाने भर की घटना नहीं है, बल्कि यह उस राजनीतिक प्रयोग की परीक्षा है, जिसने कभी व्यवस्था परिवर्तन का दावा किया था। आप का यह दौर इसलिए भी गंभीर है, क्योंकि सवाल अब व्यक्तियों से आगे बढ़कर नेतृत्व, विचारधारा और संगठनात्मक ढांचे पर उठने लगे हैं। अब जो चल रहा है वह शीर्ष नेतृत्व की विफलता को दर्शाता है। पार्टी गठन के कुछ समय बाद ही उसके संस्थापक सदस्यों का पार्टी छोड़ना शुरू हो गया था। सबसे पहले पूर्व आईपीएस किरण बेदी पार्टी से अलग हुईं, जो पार्टी का बड़ा चेहरा थीं। इसके बाद योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास, मयंक गांधी, आशुतोष, अंजलि दमानिया और अब राघव चड्ढा समेत पार्टी के सात राज्यसभा सांसदों का पार्टी छोड़ना एक बड़े बिखराव का संकेत है। इनके अलावा भी कई नाम तो लोगों की स्मृतियों से भी गायब हो चुके हैं। सात सांसदों का एक साथ पार्टी छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल को छोड़ दें तो बाकी पांच राज्यसभा सांसदों संदीप पाठक, अशोक कुमार मित्तल, हरभजन सिंह, विक्रमजीत सिंह साहनी और राजेंदर गुप्ता को किस आधार पर सांसद बनाया गया, इसका जवाब तो खुद पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के पास भी नहीं होगा।

अब इनके भाजपा में जाने पर आप दावा कर रही है कि इन लोगों ने पंजाब के लोगों के साथ विश्वासघात किया है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब पंजाब के लोगों ने इन्हें चुना ही नहीं तो विश्वासघात कैसे हुआ। इन्हें तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुना है। इस घटनाक्रम ने साबित कर दिया है कि आप में बिखराव का दौर शुरू हो चुका है। केजरीवाल का जो आकर्षण 12 साल पहले था, वह अब नहीं रहा। खासतौर पर केजरीवाल अब उन लोगों से ही मिल गए, जिन्हें वह अपनी राजनीति के शुरुआती दौर में कोसते थे। जिस खास मकसद के लिए आप का गठन हुआ, अब वह कहीं नहीं दिखता। आप अपने नाम के मुताबिक आम सी पार्टी बनकर रह गई है। यदि वास्तव में राज्यसभा के कई सांसद एक साथ पार्टी छोड़ने का निर्णय लेते हैं, तो यह संगठनात्मक असंतोष की गहराई को दर्शाता है। यह भी समझना जरूरी है कि आम आदमी पार्टी की सफलता मुख्यतः दिल्ली और पंजाब तक सीमित रही है। राष्ट्रीय स्तर पर विस्तार की जो महत्वाकांक्षा थी, वह जमीन पर साकार नहीं हो सकी। गुजरात, गोवा, उत्तराखंड जैसे राज्यों में पार्टी ने प्रयास जरूर किए, लेकिन वह स्थायी जनाधार बनाने में विफल रही। इसका कारण केवल संसाधनों की कमी नहीं, बल्कि स्थानीय नेतृत्व के अभाव और रणनीतिक अस्थिरता भी है।

इस पूरे घटनाक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अरविंद केजरीवाल की व्यक्तिगत छवि, जो कभी सादगी और संघर्ष का प्रतीक थी, अब वैसी नहीं रही। सत्ता में आने के बाद जिस तरह के समझौते और राजनीतिक व्यवहार देखने को मिले, उन्होंने उस नैतिक बढ़त को कमजोर किया है, जो पार्टी की सबसे बड़ी पूंजी थी। अब जरूरी है कि आप का नेतृत्व आत्ममंथन करे, संगठन को विकेंद्रीकृत बनाए और उन मूल सिद्धांतों की ओर लौटे, जिनके आधार पर यह आंदोलन खड़ा हुआ था। अरविंद केजरीवाल को यह समझना होगा कि करिश्मा और केंद्रीकरण के दम पर राजनीति लंबे समय तक नहीं चलती। यदि पार्टी को बचाना है तो उसे अपने मूल सिद्धांतों पारदर्शिता, आंतरिक लोकतंत्र और जवाबदेही की ओर लौटना ही होगा। अन्यथा, यह संकट एक चेतावनी नहीं बल्कि अंत की शुरुआत साबित हो सकता है।

पेसा आदिवासियों के लिए मृगतृष्णा है

कनक तिवारी

जम्हूरियत के सभी देश देख रहे हैं भारत में इन दिनों लोकतंत्र का कचूमर भी निकाला जा रहा है। हर मजबूत संस्था, व्यक्ति या समूह अपने से कमतर अधिकारों वाले व्यक्ति समूहों को दोयम दर्जे का नागरिक समझते हुए उन्हें एक तरह से अर्ध मनुष्य की तरह सलूक कर रहा है। किताबी ज्ञान स्कूली बच्चों के लिए पढ़ने में अच्छा है। गोदी मीडिया के पत्रकारों की तोतारंतत है कि भीनी भीनी सुगंध है कि भारत दुनिया में सबसे बहुसंख्यक लोकतंत्र है। भारत में जो संविधान लागू है। वह अविचल है, अडिग है। उसमें संशोधन भी जरूरत के मुताबिक होता रहता है। इसके बरक्स जमीनी हकीकत यह है कि बारायनाम लोकतंत्र केवल में ज्यादा है। व्याख्यान में है। सरकारी फाइलों में बचाव के लिए है। कुल मिलाकर जनता की समझ के धुंधले आसमान में कभी कभार दिखाई भी देता है। वरना वह गरीब आदमी के लिए आंख की किरकिरी है।

आजादी मिलने के बाद से संविधान रचने में एक कठिनाई आई कि करीब आठ से दस प्रतिशत देश की आदिवासी आबादी के लिए संविधान को जस का तस लागू नहीं किया जा सका। इन इलाकों की बनावट ऐसी है जहां पूरे संविधान की रचना के लिए अलग से सोचना पड़ा। यही कारण है संविधान में पांचवीं और छठी अनुसूची में देश के आदिवासी इलाकों के लिए अलग से प्रावधान किए गए। पूर्वोत्तर की छठी अनुसूची वहां के आदिवासियों को काफी अधिकार देती है लेकिन भारत के शेष भाग के जिन इलाकों में पांचवीं अनुसूची का बोलबाला है। वहां आज भी आदिवासी अविकसित होकर निर्वासियों की तरह जीने को आंशिक रूप से मजबूर हैं। संविधान निर्माताओं ने एक बात और नहीं सोची थी कि इन आदिवासी इलाकों में कभी जल, जंगल और जमीन की डकैती हो सकेगी। सरकारें अधिनियम बनाएंगी और हर वनोत्पाद पर सरकारी नियंत्रण हो जाएगा। फिर दलाली की भूमिका वाले अरबपति, खरबपति, कॉरपोरेट घरानों को उनकी मिल्कियत बनाकर सौंप दिया जाएगा। इसका एक कारण यह भी था कि संविधान सभा ने गांधी की सिफारिश के मुताबिक पंचायत राज लागू करने से इंकार कर दिया था। हालांकि राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में इस पर पुनर्विचार हुआ और शहरी तथा पंचायती संस्थाओं को अहमियत दी गई।

आदिवासियों और जनता को भी भ्रम रहा है। फिर भी आदिवासियों के बार बार आग्रह के कारण संसद में 24 दिसम्बर 1996 को पंचायत राज उपबंध अधिनियम तथा अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार अधिनियम बना। वह पेसा के लोकप्रिय नाम से आदिवासियों से उसी तरह छल कर रहा है जैसा कभी अंग्रेजों ने किया होगा। नेताओं को भ्रम है कि पेसा के तहत संसद में आदिवासियों की सुरक्षा के कई प्रबंध किए गए हैं। दरअसल इसे रचने के पहले सांसद दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने जानदार और महत्वपूर्ण सिफारिशें कीं। उनसे आदिवासियों का जीवन और उनकी गरिमा सुरक्षित रह सकती थी। दिलीप सिंह भूरिया समिति का सबसे महत्वपूर्ण तर्क था कि उनके इलाकों में आदिवासियों का कुदरती संसाधनों पर नियंत्रण और कमांड नैसर्गिक अधिकार है। यह एक ऐतिहासिक तथ्य भी रहा है। सभी सिफारिशें संसद ने कबूल नहीं कीं। भूरिया समिति ने कहा था कि पंचायती संस्था का ढांचा भी इसी तरह बनाया जाए कि उनमें आदिवासियों के जीवन और संगठन, सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों और सामुदायिक भावना को शामिल किया जाए। फिर भी केन्द्र सरकार ने इसे कारगर नहीं किया। अनुच्छेद 39 संविधान में कहता रहा कि संपत्ति के अधिकार का संकेन्द्रण नहीं होगा लेकिन उसका मजाक उड़ाया गया। हकीकत यह है कि पेसा के तहत ग्रामसभा कोई शक्तिशाली संस्था नहीं है। उसे बहुत सीमित अधिकार हैं और उनको भी आसानी से समयानुसार विलोपित भी कर लिया जाता है। कलेक्टर और कप्तान साहब तो बड़े अधिकारी हैं। आदिवासी इलाकों में जंगल, आबकारी, राजस्व, खनिज विभाग के छोटे छोटे अधिकारी भी माइ लॉर्ड होते हैं।

यह दिलचस्प रहा है कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेसी सरकार के उपमुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री टी. एस. सिंहदेव बस्तर सहित कई इलाकों में धमक के साथ कहते रहे कि पेसा के तहत जो भी अधिकार हैं। वे आदिवासी इलाकों की ग्राम पंचायतों को सौंपे जाने की सरकार की मुहिम है। टांय टांय फिस्स तो फिर हुआ कि शक्तिशाली पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के इशारे पर कहा जाता है कि संबंधित जिले के कलेक्टर और जिलों के पुलिस अधीक्षक पंचायत मंत्री से मिले तक नहीं। फिर क्या खाक क्रांति होती। आदिवासी विधायक और सांसद केवल मिन्नतें करते हैं। हाथ जोड़ते हैं। चिल्लपों मचाते हैं लेकिन पांचवीं अनुसूची में गवर्नरों को इतने अधिकार हैं कि वह केवल उनसे बातचीत करें। सुनें और पढ़ें और फिर करें केवल अपने मन की। क्या इसे संसदीय अधिकार कहा जा सकता है? सारी ताकत इस बात पर अटकती है कि ग्राम सभा की मंजूरी के बिना कोई औद्योगिक निर्माण नहीं होगा। देश के लोगों को तो सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा पूरा नहीं है। लेकिन कभी तो था। सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कोई फैसला नहीं है जो पेसा कानून की इस तरह समीक्षा करे कि जल, जंगल, जमीन में जितनी प्राकृतिक संपदा है। वह सब उन आदिवासी इलाकों की है। जो वहां रहते हैं। उनकी मर्जी के बिना न तो उसे लिया जा सकता है और न ही वहां औद्योगिकीकरण हो सकता है। फुसलाने के नाम पर सही है कि जहां आदिवासियों की परंपरा के मुताबिक कोई मंदिर या पूजा स्थल है। वहां उनकी बात जरूर सुनी जाए।

इस देश के आदिवासी को तो अब अपना अस्तित्व खत्म होने की कगार पर लगने लगा है। पूरा बस्तर लुट जाने के खतरे में है। भारत में आदिवासियों की सबसे बड़ी आबादी बस्तर और छत्तीसगढ़ में है। क्या यह इलाका अब बिना पेड़ों, खनिज और अन्य फसलों के साथ रहेगा? ऐसा खतरा लगता रहा है। तब आदिवासी कहां रहेंगे। क्या वे बचेंगे। ऐसा खतरा अब दुनिया में सभी लोगों के सामने भी खड़ा हो गया है। जब तक आदिवासियों के प्रतिनिधियों की सलाहकार समिति को अधिकार नहीं मिलेंगे। जिनकी मुमानियत गवर्नर और राज्य सरकार नहीं कर सकें। बल्कि केन्द्र सरकार भी नहीं कर सके। तब ही देश में आदिवासी बचेगा। वरना पेसा कानून तो फकत मसिंया गा रहा है। उसे जन्मदिन की बधाई या विवाह के मांगलिक कार्य के संगीत की तरह नहीं समझा जा सकता। आदिवासी भी भ्रम में हैं क्योंकि देश के बुद्धिजीवी और पत्रकार भी ठीक से संसूचित नहीं करते हैं। सरकार में तो शातिर नौकरशाह हैं। उनकी पीठ पर वरद हस्त रखने वाले कॉरपोरेटियों की ताकत है। लोकतंत्र बेचारा क्या करेगा? बस किताबों की जिल्द में रहेगा। बच्चे उसे पढ़ते रहेंगे। परीक्षा में पास होंगे लेकिन उनके जीवन को समझने में इतिहास ही असफल होता रहेगा।

जानिए कैसे चेतना को विस्तृत करता है योग?

योग के आठ अंग हैं और उनमें से मात्र एक अंग है शारीरिक मुद्राएं या आसन। योग मात्र व्यायाम नहीं है, इसमें मुख्य बात मन की समरसता को बनाए रखना है। जब आप कोई भी कार्य सजगता से करते हैं, तब आप इस बात के प्रति सजग होते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। यही आपको योगी बनाता है। योग के प्रतिपादक पतंजलि ने बताया है कि योग का उद्देश्य दुख को आने से पहले ही दूर कर देना है। लालच, क्रोध, जलन, घृणा, निराशा आदि नकारात्मक भावनाओं को योग से मिटाया जा सकता है। जब आप खुश होते हैं, तब आप अपने भीतर एक विस्तार की भावना का अनुभव करते हैं। विफलता या अपमान की स्थिति में लगता है कि हमारे भीतर कुछ सिकुड़ गया है। इस पर ध्यान देना ही योग है, जिसका हमारे खुश हो जाने पर विस्तार होता है और जो हमारे दुखी हो जाने पर सिकुड़ जाता है। मन की इस स्थिति को परिवर्तित करने का रहस्य योग में है। यह आपको स्वतंत्र बनाता है। अपनी ही भावनाओं के द्वारा पीड़ित होने के बजाय आप जिस समय जैसा महसूस करना चाहते हैं, योग उसके लिए आपको शक्ति प्रदान करता है। योग निश्चित रूप से आपको अधिक जिम्मेदार बनाता है, क्योंकि योग से आपके भीतर ऊर्जा एवं उत्साह उत्पन्न होता है। आप तब जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, जब आप थके हुए और तनावग्रस्त होते हैं। यदि आपने अपनी थकान और तनाव को संभाल लिया, तब आप निश्चित रूप से अधिक जिम्मेदारी उठाएंगे और आपके भीतर हल्कापन भी बना रहेगा।

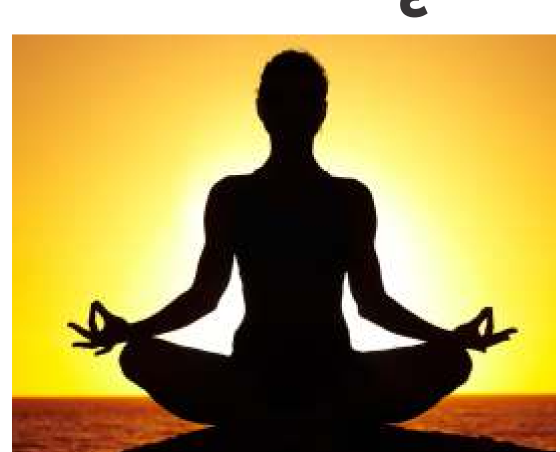

कैसे आम आदमी पार्टी में तैयार हुआ टूट का प्लॉट?

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी (AAP) को शुक्रवार को बड़ा राजनीतिक झटका लगा, जब उसके 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों ने पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया. पार्टी छोड़ने वालों में राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी और स्वाति मालीवाल शामिल हैं. इस घटनाक्रम ने संसद में AAP की स्थिति को कमजोर कर दिया है और पार्टी के राष्ट्रीय भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं.

स्वाति मालीवाल विवाद: टूट की शुरुआत

AAP के मौजूदा संकट की जड़ें साल 2024 में सामने आए उस विवाद से जुड़ी हैं, जब स्वाति मालीवाल ने तत्कालीन दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी सहयोगी पर उनके आवास पर शारीरिक हमला करने का आरोप लगाया था. 13 मई 2024 को सामने आए इस मामले ने पार्टी के अंदर गहरी दरार पैदा कर दी, जो समय के साथ और चौड़ी होती गई. इस महीने की शुरुआत में पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में उपनेता पद से हटा दिया. इस फैसले ने उनके और पार्टी नेतृत्व के बीच दूरी को और बढ़ा दिया. इसके बाद सुलह की संभावनाएं लगभग खत्म होती नजर आईं.

'भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी' के आरोप

पार्टी छोड़ते हुए स्वाति मालीवाल ने एक विस्तृत पोस्ट में "बेकाबू भ्रष्टाचार" का आरोप लगाया. उन्होंने महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न और हमले की घटनाओं का भी जिक्र किया और आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पार्टी "गुंडा तत्वों" को बढ़ावा दे रही है. इन आरोपों ने विवाद को और गहरा कर दिया है.

चौंकाने वाला सामूहिक इस्तीफा

हालांकि कुछ नेताओं के नाराज होने की चर्चाएं पहले से थीं, लेकिन एक साथ सात सांसदों का इस्तीफा देना चौंकाने वाला रहा. अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, राजेंद्र गुप्ता, विक्रम साहनी और संदीप पाठक जैसे नेताओं ने असहमति नहीं जताई थी.

ED छापों के बाद मित्तल का फैसला

अशोक मित्तल का इस्तीफा उनके घर और कारोबारी ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) के छापों के बाद आया. ये छापे विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) से जुड़े मामले में डाले गए थे, जिससे राजनीतिक दबाव की अटकलें और तेज हो गईं.AAP नेता संजय सिंह ने इस पूरे घटनाक्रम के पीछे बीजेपी पर "ऑपरेशन लोटस" चलाने का आरोप लगाया. उनका कहना है कि ED और CBI जैसी एजेंसियों के डर से सांसदों ने पार्टी छोड़ी. सिंह के मुताबिक, इस्तीफों का समय और पैमाना बाहरी दबाव की ओर इशारा करता है.

हरभजन सिंह के घर के बाहर आप कार्यकर्ताओं ने दीवार पर लिखा 'गद्दार'

पंजाब में आम आदमी पार्टी (AAP) के कई राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद सियासी माहौल गरमा गया है. पार्टी के कार्यकर्ताओं में इस फैसले को लेकर भारी नाराजगी देखी जा रही है. इसी बीच AAP के कई कार्यकर्ताओं ने पूर्व क्रिकेटर और राज्यसभा सांसद हरभजन सिंह के खिलाफ गुस्सा जाहिर किया. कार्यकर्ताओं ने उनके घर के बाहर दीवारों पर 'गद्दार' लिखकर विरोध दर्ज कराया.बताया जा रहा है कि AAP के सात राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा, संदीप पाठक, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, राजिंदर गुप्ता, अशोक मित्तल और विक्रम साहनी ने बीजेपी का दामन थाम लिया है. इस कदम के बाद पार्टी के अंदर गहरा संकट पैदा हो गया है. आम आदमी पार्टी (AAP) छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (BJP) में शामिल हुए पंजाब के राज्यसभा सांसदों के मुद्दे पर अब सियासी हलचल तेज हो गई है. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस मामले को लेकर बड़ा कदम उठाया है. पार्टी सूत्रों के मुताबिक, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शनिवार को पार्टी विधायकों के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के लिए समय मांगा है. इस मुलाकात में वह अपनी पार्टी का पक्ष रखने वाले हैं. सूत्रों के अनुसार, इस दौरान भगवंत मान उन राज्यसभा सांसदों की सदस्यता समाप्त करने की मांग उठाएंगे, जिन्होंने AAP छोड़कर BJP जॉइन कर ली है. यह पूरा घटनाक्रम उस समय सामने आया जब पंजाब से चुने गए छह सांसदों समेत कुल सात राज्यसभा सदस्यों ने BJP में शामिल होने का ऐलान किया

अमेरिका में बोले दत्तात्रेय होसबोल- RSS ना अल्पसंख्यक विरोधी और ना महिला विरोधी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने वॉशिंगटन में कहा कि

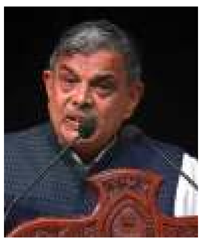

विदेशों में बसे भारतीय प्रवासियों को उस देश के प्रति पूरी तरह वफादार रहना चाहिए जहां वर्तमान में वे रह रहे हैं. होसबोले ने कहा कि विदेशों में बसे भारतीय न सिर्फ अपने वर्तमान देश का बेहतर नागरिक बनने का प्रयास करें बल्कि यह भी सिद्ध करें कि हिंदू समाज स्थानीय जीवन के हर क्षेत्र में-चाहे वह नेतृत्व हो, समाजसेवा हो या कोई और दायित्व-सार्थक योगदान देने में सक्षम है. अमेरिका की यात्रा पर आए होसबोले ने कहा कि यहां उनकी बातचीत का केंद्र संघ के बारे में फैली भ्रांतियों को दूर करना रहा. उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों से संघ के विरुद्ध जारी दुष्प्रचार के कारण अमेरिकियों के मन में इस 100 पुराने संगठन की एक विकृत छवि बन गई है. होसबोले ने कहा, "इन तमाम वर्षों में संघ इस विश्वास के साथ चुपचाप काम करता रहा कि हमारा काम ही हमारा संदेश है लेकिन अब हमने सोचा कि लोगों तक सीधे पहुंचना बेहतर होगा.

ईरान अमेरिका से दोबारा क्यों नहीं कर रहा बात?

नई दिल्ली। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर की आखिरी तारीख पार हो चुकी है. हालांकि अभी तक दोनों ही देश दूसरी बार बातचीत के लिए एक ही टेबल पर साथ नहीं आ पाए हैं. अमेरिका का डेलीगेशन इस वक्त पाकिस्तान में है. वहीं ईरान की तरफ से भी डेलीगेशन आया है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया के सूत्रों के मुताबिक ईरानी डेलीगेशन अमेरिका के साथ दूसरे दौर की बात करने को तैयार नहीं है. उसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक बड़ी शर्त रखी है.

दरअसल ईरानी डेलीगेशन ने स्पष्ट कह दिया है कि अमेरिका के साथ दूसरे दौर की बातचीत तब तक नहीं हो सकती है, जब तक वह अपना नेवल ब्लाकेड स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से नहीं हटा देता है. ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची के नेतृत्व वाला ईरानी प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान के तीनों सेनाओ के प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अध्यक्षता वाले डेलीगेशन के साथ मुलाकात करके एक लिखित फ्रेमवर्क भी दे चुका है.

अमेरिका-ईरान के बीच किन बातों पर फंसा पेंच

अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से बंद कर दे, लेकिन ईरान इसके लिए तैयार नहीं है. पहले दौर की बातचीत के दौरान भी इसी बात पर मामला अटक गया था. इसके साथ-साथ होर्मुज के मसले पर भी बात नहीं बन पायी थी. अब ईरान का कहना है कि दूसरे दौर की बात तभी होगी जब होर्मुज से अमेरिकी नेवी हट जाएगी.

ईरान-पाकिस्तान की बातचीत में कौन-कौन रहा शामिल

ईरान के डेलीगेशन से उसी पाकिस्तानी डेलीगेशन ने बातचीत की है जो कि तेहरान गया था. इसमें DG-ISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक, D G M O काशिफ अब्दुल्ला, गृहमंत्री मोहसिन नकवी और आसिम मुनीर के प्राइवेट सेक्रेटरी मेजर जनरल सैयद जवाद तारिक शामिल थे. अगर ईरानी डेलीगेशन की बात करें तो इसमें विदेश मंत्री अब्बास अराघची के अलावा उप विदेश मंत्री काज़ेम ग़रीबाबादी, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई और पाकिस्तान में ईरानी राजदूत रेज़ा अमीरी मोघदम शामिल थे.

बैठक के बाद पाक विदेश मंत्रालय ने जारी किया बयान

ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान की मध्यस्था में प्रस्तावित बातचीत को लेकर विदेश मंत्री इशाक डार ने 25 अप्रैल को अधिकारियों के साथ बैठक की. बैठक के बाद पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके लिखा कि में विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा कि ईरान-अमेरिका वार्ता में पाकिस्तान की भूमिका को लेकर आधिकारिक नीति केवल सरकारी स्रोतों द्वारा जारी की जाती है.

159 बिलियन डॉलर की वापसी पर क्या बोले ट्रंप?

ट्रंप ने जिन देशों से वसूला टैरिफ, अब वो रकम करनी पड़ेगी वापस!

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद देश को करीब 159 बिलियन डॉलर का टैरिफ वापस करना पड़ सकता है. उन्होंने इस फैसले को भयानक और हास्यास्पद बताया है. यह मामला उन टैरिफ से जुड़ा है जो 2025 में ट्रंप सरकार की व्यापार नीति के तहत लगाए गए थे. उस समय अमेरिका ने कई देशों से आने वाले सामान पर अतिरिक्त शुल्क लगाया था, जिससे सरकार को बड़ी रकम मिली थी.

हालांकि, बाद में ट्रंप के इस फैसले को अदालत में चुनौती दी गई. कोर्ट ने कहा कि प्रशासन ने टैरिफ लगाने में अपने अधिकार से ज्यादा कदम उठाया है, यानी जो अधिकार सरकार के पास थे उससे आगे जाकर यह फैसला लिया गया था. सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद अब स्थिति यह बन गई है कि अमेरिका को उन देशों को यह पैसा वापस करना पड़ सकता है, जिनसे यह टैरिफ लिया गया था. यह रकम लगभग 159 बिलियन डॉलर बताई जा रही है, जो बहुत बड़ी मानी जाती है.

ट्रंप ने जताई नाराजगी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह गलत है और इससे अमेरिका को नुकसान होगा. उनका मानना है कि यह टैरिफ देश के हित में लगाया गया था, लेकिन कोर्ट ने इसे गलत ठहरा दिया. अब आगे यह देखना होगा कि इस फैसले को कैसे लागू किया जाता है और किन देशों को कितना पैसा वापस किया जाएगा. यह मामला अंतरराष्ट्रीय व्यापार और अमेरिका की आर्थिक नीति दोनों पर असर डाल सकता है.बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के तमाम देशों पर भारी-भरकम टैक्स लगाया था, जिसमें भारत, चीन, तुर्किए, कनाडा, जापान, इजरायल समेत मेक्सिको जैसे तमाम देश शामिल थे. शुरुआत में भारत पर 50 फीसदी का टैरिफ लगाया गया था. हालांकि, बाद में ट्रेड डील पूरा की वजह से टैक्स 18 फीसदी तक हो गया.

चुनाव के बीच कोलकाता समेत 7 ठिकानों पर ईडी के छापे

नई दिल्ली। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी पीडीएस गेहूं घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पश्चिम बंगाल में कई जगहों पर छापेमारी की है. शुक्रवार को ईडी की कोलकाता जोन की टीम ने कोलकाता, बर्धमान और हावड़ा समेत कुल 9 ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया. यह कार्रवाई निरंजन चंद्र साहा और उससे जुड़े सप्लायर्स, डीलर्स और एक्सपोर्टर्स के खिलाफ की जा रही है. ईडी की यह जांच पश्चिम बंगाल पुलिस की ओर से दर्ज एक एफआईआर के आधार पर शुरू हुई थी. यह एफआईआर 23 अक्टूबर 2020 को बसीरहाट थाने में दर्ज की गई थी, जिसमें घोजाडांगा एलसीएस के डिप्टी कमिश्नर ऑफ कस्टम्स ने शिकायत दी थी. जांच में सामने आया है कि गरीबों और जरूरतमंदों के लिए सरकारी योजना के तहत भेजे जाने वाले गेहूं की बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई. आरोप है कि इस गेहूं को सस्ते दामों पर अवैध तरीके से खरीदा गया और फिर सप्लायर्स, डीलर्स और बिचौलियों की मिलीभगत से बाजार में ऊंचे दाम पर बेचा गया।

पंजाब ने किया आईपीएल का सबसे बड़ा रन चेज़

4 विकेट खोकर हासिल किया 265 रन का लक्ष्य

नई दिल्ली। दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पंजाब किंग्स ने रिकॉर्ड रन चेज कर दिया है। दिल्ली ने पंजाब के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए 264 रनों का स्कोर खड़ा किया था। पंजाब ने इसे हासिल कर लिया और आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा रन चेज कर डाला। उन्होंने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा है। इससे पहले आईपीएल में सबसे बड़ा रन चेज करने का रिकॉर्ड भी पंजाब के नाम पर दर्ज था।

पंजाब ने रिकॉर्ड चेज को 7 गेंद शेष रहते ही अंजाम दिया। दिल्ली के लिए केएल राहुल ने शतक लगाया था और ऐतिहासिक पारी खेली थी लेकिन पंजाब ने उनकी इस पारी पर पानी फेर दिया। पंजाब के लिए प्रभसिमरन सिंह और कप्तान श्रेयस अय्यर ने कमाल की पारी खेली। इसी वजह से पंजाब की टीम इतिहास रचने में कामयाब रही और उन्होंने रिकॉर्ड रन चेज कर दिया।

पंजाब ने दिल्ली के खिलाफ 18.5 ओवरों में 265 रनों के लक्ष्य को हासिल किया। ये आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा चेज है। इससे पहले भी ये रिकॉर्ड पंजाब के नाम पर ही दर्ज था। पीबीकेएस ने आईपीएल 2024 में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 262 रनों का चेज किया था। अब पंजाब ने अपने उसी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था। इसके बाद केएल राहुल के 152 रनों की बदौलत दिल्ली ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 2 विकेट के नुकसान पर 264 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। इस स्कोर को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि दिल्ली मुकाबले में जीत हासिल कर लेगी पंजाब ने कुछ अलग कर दिखाया। पंजाब ने 265 रनों के लक्ष्य को 18.5 ओवरों में हासिल कर लिया और जीत हासिल की। पंजाब के लिए सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्या ने शानदार शुरुआत की। दोनों ने पावरप्ले में ही 116 रन ठोक डाले थे। प्रियांश ने 17 गेंदों पर 43 रनों की पारी खेली, जबकि प्रभसिमरन ने 76 रन बनाए। कप्तान श्रेयस अय्यर ने कप्तानी पारी खेलते हुए नाबाद 71 रन बनाए।

Paytm पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द, क्या अब पेमेंट नहीं कर पाएंगे लोग?

नई दिल्ली। पेटीएम को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है. इसका मतलब है कि पेटीएम अब भविष्य में बैंकिंग से जुड़ा कारोबार नहीं कर पाएगा. आरबीआई ने कहा है कि पेटीएम बार-बार लाइसेंस शर्तों का उल्लंघन कर रहा था. इसके बाद गंभीर नियामक चिंताओं को देखते हुए कंपनी का बैंकिंग लाइसेंस रद्द करना पड़ा. आरबीआई के इस कदम के बाद हर किसी के मन में सवाल है कि अब पेटीएम एप से पेमेंट हो पाएगा या नहीं. जानिए. पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द होने का असर पेटीएम यूजर्स पर भी पड़ेगा. अब लोग पेटीएम बैंक में नया पैसा जमा नहीं कर पाएंगे. इससे आपके सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट और वॉलेट में मौजूद सेवाओं पर सीधा असर पड़ेगा. कई छोटे दुकानदार और रेहड़ी-पटरी वाले Paytm बैंक का ही इस्तेमाल करते थे, उनके लिए अचानक पेमेंट रिसीव करने और सेटलमेंट करने में दिक्कतें आ सकती हैं. हालांकि पेटीएम से डायरेक्ट पेमेंट करने के लिए बैंक लिंक होना जरूरी है. ऐसे में जब आप क्यूआर कोड के जरिए पेमेंट करते हैं तो पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट से कटता है. ऐसे में इसपर लाइसेंस रद्द होने का असर नहीं पड़ेगा.

FASTag रिचार्ज मुश्किल!

लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर आपका FASTag या वॉलेट पेटीएम बैंक से लिंक है तो उसे रिचार्ज करना या इस्तेमाल करना मुश्किल हो जाएगा. हालांकि लाइसेंस रद्द करना इस बात का संकेत है कि सरकार आपके पैसे को किसी बड़े जोखिम में डूबने से बचाना चाहती है. ऐसी सख्ती से अन्य बैंक भी सतर्क रहेंगे और नियमों का पालन करेंगे, जिससे भविष्य में किसी बड़े बैंकिंग घोटाले की संभावना कम होगी.

फिर गूंजी 'थप्पड़कांड' की आवाज, श्रीसंत के बयान से मचा बवाल

नई दिल्ली। आईपीएल 2026 के बीच एक बार फिर हरभजन सिंह और श्रीसंत के 'थप्पड़कांड' की आवाज गूंज उठी है. 2008 में हुए विवाद ने उस वक्त काफी सुर्खियां बटोरी थीं. अब श्रीसंत के बयान से एक बार फिर यह वाकया सुर्खियों में आ गया है. दरअसल श्रीसंत ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भज्जी ने थप्पड़कांड पर आधारित एक विज्ञापन से करीब 1 करोड़ रुपये कमाए हैं. \श्रीसंत ने कहा कि अब उन्होंने हरभजन को इंस्टाग्राम पर ब्लॉक भी कर दिया है. तो आइए जानते हैं कि पूरा माजरा क्या है. इंडिया टुडे के हवाले से श्रीसंत ने कहा, "मैंने कभी किसी इंटरव्यू में भज्जी को लेकर बात नहीं की, जब तक कोई विवाद नहीं था. लेकिन उन्होंने उस बारे (थप्पड़कांड) में एक विज्ञापन से 1 करोड़ रुपये कमाए।

अडानी की दौलत में जबरदस्त उछाल 100 बिलियन डॉलर क्लब में एंट्री

नई दिल्ली। भारत के दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी की संपत्ति में हाल के दिनों में तेज बढ़ोतरी देखने को मिली हैं. ब्लूमबर्ग बिलेनियर इंडेक्स के अनुसार उनकी नेटवर्थ करीब 106 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई थी. जिसके बाद वे दुनिया के अमीरों की सूची में 17वें स्थान पर आ गए थे. संपत्ति के मामले में गौतम अडानी ने Bill Gates को भी पीछे छोड़ दिया था. हालांकि, संपत्ति में हुई गिरावट की वजह से वे फिर इस पायदान से फिसल गए हैं. इसके बावजूद भी वे 100 बिलियन डॉलर से ज्यादा संपत्ति रखने वाले खास क्लब में भी शामिल हो चुके हैं और दुनिया के 18वें सबसे अमीर आदमी हैं. जहां दुनिया के गिने-चुने लोग ही पहुंच पाते हैं.

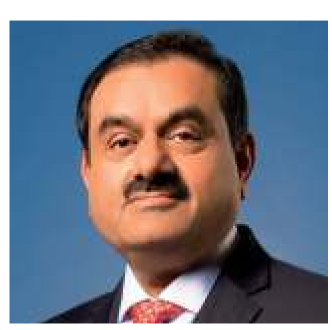

एक दिन में 59,000 करोड़ की बढ़त

ब्लूमबर्ग बिलिनेयर इंडेक्स के मुताबिक, Gautam Adani की संपत्ति में एक ही दिन में करीब 7.16 अरब डॉलर यानी करीब 59,000 करोड़ रुपये का इजाफा हुआ है. इसके बाद उनकी कुल नेटवर्थ बढ़कर 106 अरब डॉलर यानी करीब 10 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई थी. जिससे वे दुनिया के अमीरों की सूची में 17वें पायदान पर आ गए थे. साल 2026 की बात करें तो अब तक उनकी कुल संपत्ति में करीब 21.4 अरब डॉलर, भारतीय रुपयों में करीब 2 लाख करोड़ से ज्यादा की बढ़त देखने को मिली है.

अब चावल के बाजार पर संकट! सप्लाई हुई ठप

नई दिल्ली। यूएस और ईरान के बीच चल रहे तनाव के कारण दुनियाभर के बाजारों का हाल बेहाल है. पेट्रोल-डीजल और क्रूड ऑयल की कमी और कीमतों में वृद्धि से जनता परेशान है. तो वहीं अब चावल का निर्यात भी प्रभावित हो रहा है. वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक मध्य पूर्व के देशों समेत कई रास्तों पर शिपमेंट में कमी देखने को मिली है. जिसकी वजह से एक्सपोर्ट में तेजी से गिरावट आई है. भारत ग्लोबल लेवल पर चावल का बड़ा उत्पादक है, लेकिन फिलहाल के हालातों को देख ये बाजार ठप सा नजर आ रहा है. हाल ही में आई वाणिज्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक चावल निर्यात वित्त वर्ष 2025-26 में 7.5 प्रतिशत घटकर 11.53 अरब डॉलर ही बचा है. वहीं बात करें मार्च की तो इस महीने में 15.36 प्रतिशत से घटकर निर्यात 99.75 करोड़ डॉलर पर पहुंच गाय है.ईरान सबसे ज्यादा मात्रा में भारत से बासमती चावल खरीदता है. लेकिन फिलहाल की स्थिति को देखते हुए ऑर्डर का फ्लो, पेमेंट फ्लो और शिपमेंट शेड्यूल काफी प्रभावित हो रहा है. तो वहीं ईरान, UAE, सऊदी अरब और ओमान समेत मध्य पूर्व क्षेत्र के देशों को होने वाली शिपमेंट भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो रही है.

8वां वेतन आयोग: कितना होगा न्यूनतम वेतन?

नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए आठवें वेतन आयोग की चर्चाएं तेज हो गई हैं. ऐसा कहा जा रहा है कि इसमें कर्मचारियों की मिनिमम बेसिक सैलरी में बंपर उछाल आ सकता है. इसी क्रम में 28 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच दिल्ली में बैठकों का एक दौर शुरू होने जा रहा है. 24 अप्रैल की एक नोटिस में आयोग ने कहा कि उसे कर्मचारी संघों और एसोसिएशनों से 28 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच दिल्ली में होने वाली बैठकों के लिए बड़ी संख्या में अनुरोध मिले हैं. समय की कमी के चलते इस दौरान सभी अनुरोधों को पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन आयोग ने आश्वासन दिया है कि आने वाले महीनों में दिल्ली के साथ-साथ विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी और बैठकें आयोजित की जाएंगी।

AI के जमाने में ऐसी नौकरियां सबसे ज्यादा सुरक्षित जिनमें हुनर की जरूरत

अगले 50 सालों में भी AI नहीं खा पाएंगी ये नौकरियां

नई दिल्ली। AI (Artificial Intelligence) का दौर जब से शुरू हुआ है, तब से छंटनी की खबरें अकसर ही सुनने को मिल रही हैं. ऐसे में लोग इस खौफ में जी रहे हैं कि कहीं अगला नंबर उनका न हो. ऐसा कहा जा रहा है कि अगले 50 सालों में ऐसी कोई भी नौकरी नहीं है, जो AI से 100 परसेंट सिक्योर्ड हो. Reddit पर मिले जवाबों से पता चलता है कि आजकल लोगों का उन नौकरियों पर ज्यादा भरोसा है, जिनमें इंसानी तौर-तरीके, कौशल और बातचीत करने की जरूरत हो. जैसे-जैसे AI का दायरा बढ़ेगा, ये नौकरियां उसका अच्छे से सामना कर पाएंगी.

AI से सुरक्षित नौकरियां

Reddit यूजर्स को लगता है कि AI के इस जमाने में ऐसी नौकरियां सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, जिनमें हुनर की जरूरत पड़ती है जैसे कि प्लंबर, हेल्थकेयर से जुड़ी नौकरियां जैसे नर्स, थेरेपिस्ट, दाई और लाइसेंस वाले पेशे जैसे डॉक्टर और वकील.यूजर्स का मानना है कि आने वाले समय में AI इन नौकरियों की जगह पूरी तरह से नहीं ले पाएगा. एक यूजर ने कहा, "मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं और मुझे अपने करियर के भी 5 साल से ज्यादा चलने की उम्मीद नहीं है. हर चीज इतनी तेजी से ऑटोमेट हो रही है. इस समय, अगर लंबे समय तक टिकने की बात हो, तो मैं कोडर के बजाय प्लंबर पर दांव लगाऊंगा."

AI का इन जॉब्स पर नहीं असर

- प्लंबर, टेक्नीशियन और बढ़ई के काम में इंसानी हुनर की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है. किसी पुरानी इमारत की मरम्मत या दीवारों के पीछे की वायरिंग को ठीक करना फिलहाल AI के बस की बात नहीं.
- नर्स, थेरेपिस्ट, सर्जन, डेंटिस्ट की जगह भी AI नहीं ले सकता. AI बेशक बीमारी का पता लगा सकता है, लेकिन मरीज का इलाज करने, उसे सहारा देने और उसकी भावनाओं को समझने में AI नाकाम साबित होगा.
- HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) और वेल्डिंग जैसे काम सेंसरी फीडबैक पर निर्भर करते हैं. इनके लिए श्रमिक को खुद को अलग-अलग स्थितियों में ढालना पड़ता है, जो AI या रोबोट्स से परे है.

विधानसभा के विशेष सत्र पर गरमाई सियासत

मप्र में भी सत्र लेकिन निंदा का जिक्र नहीं

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 30 अप्रैल को होने वाले विशेष सत्र को लेकर राज्य की सियासत गरमाई है. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि इस सत्र में निंदा प्रस्ताव पारित किया जाना है, दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष डा. चरणदास महंत ने सवाल किया है कि कैसे निंदा प्रस्ताव ला सकते हैं. दूसरी ओर मप्र में 27 अप्रैल को विशेष सत्र रखा गया है, लेकिन वहां होने वाली कार्यवाही में निंदा प्रस्ताव जैसे किसी शब्द का जिक्र ही नहीं है

सीएम साय ने कही ये बात

जिस प्रकार हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी देश के विकास में माताओं बहनों को 33 प्रतिशत नेतृत्व 2020 से सुनिश्चित करना चाहते थे, उसके लिए संसद में जो विधेयक लाया गया था, उसे पारित कराने में इंडी गठबंधन ने साथ नहीं दिया और 70 करोड़ महिलाओं के साथ अन्याय किया. इसके विरोध में निंदा प्रस्ताव पारित किया जाना है. इस हेतु 30 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र आहूत किया गया है. विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर सत्ताधारी भाजपा द्वारा शुरू से कहा जा रहा है कि इस सत्र में निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा, लेकिन विधानसभा की ओर से जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि शासकीय कार्य के लिए यह सत्र बुलाया गया है. अब सवाल ये उठ रहा है कि शासकीय कार्य क्या है. इस मामले को लेकर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है, लेकिन इसी तरह का सत्र मप्र विधानसभा में भी लाया जा रहा है, वहां की कार्य सूची में भी निंदा प्रस्ताव जैसी कोई बात नहीं है.

महंत ने कहा- ये चिंता की बात

विशेष सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष डा. चरणदास महंत का बयान सामने आया है. उन्होंने कहा- महामहिम का आमंत्रण पत्र आया है. जाना तो पड़ेगा. चिंता इस बात की है कि मुख्यमंत्री ने कहा था निंदा प्रस्ताव लाएंगे तो कैसे ला सकते है. निंदा प्रस्ताव.. क्या होता है कैसे लाएंगे. पता नहीं किस अकलमंद सलाहकार ने उन्हें इस बात की सलाह दी है. आखिर निंदा प्रस्ताव आप कैसे लाएंगे लोकसभा की कार्यवाही के खिलाफ? क्या उसे सदन में हुई चीजों को यहां चर्चा किया जाएंगे? समझ से बाहर है. बाकी सदन की चर्चा में भाग लेंगे जवाब भी देंगे।

महंत को किरण सिंहदेव ने दिया ये जवाब

नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव ने कहा- नेता प्रतिपक्ष को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए. कांग्रेसी नहीं चाहते कि महिलाओं को कोई लाभ हो. कांग्रेस नहीं चाहती महिलाओं का आक्रोश बाहर आए. हम विधानसभा के विशेष सत्र में इस पर चर्चा करेंगे।

विशेष सामान्य सभा की वैधानिकता पर पूर्व महापौर ने उठाए सवाल

रायपुर। पूर्व महापौर एजाज ढेबर ने रायपुर नगर निगम की विशेष सामान्य सभा की वैधानिकता पर सवाल उठाए हैं। वहीं आरोप लगाया कि पानी, सफाई, सड़क के मुद्दे पर भाजपा खामोश है। विशेष सभा के बहाने भाजपा केवल राजनीति कर रही है। विशेष सामान्य सभा का उद्देश्य आपातकालीन और जनहित के मुद्दों पर चर्चा करना होता है लेकिन वर्तमान में इसका उपयोग राजनीतिक एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। श्री ढेबर ने पूछा कि शारदा चौक-तात्यापारा चौक सड़क चौड़ीकरण जैसे महत्वपूर्ण और लंबे समय से लंबित मुद्दे पर, जिसकी मांग सभी दलों के पार्षदों ने की है, उस पर विशेष सामान्य सभा क्यों नहीं बुलाई गई? वहीं शहर में पानी, सफाई और गर्मी से राहत जैसे गंभीर विषयों पर भी चर्चा से क्यों बचा जा रहा है। उन्होंने नगर निगम के सभापति से पूछा कि क्या यह विशेष सामान्य सभा वास्तव में संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है या सिर्फ राजनीतिक निर्देशों पर आयोजित की जा रही है? पूर्व महापौर ने मांग उठाई कि विशेष सामान्य सभा को जनता से जुड़े वास्तविक मुद्दों सड़क चौड़ीकरण, पेयजल, सफाई और स्वास्थ्य पर केंद्रित किया जाए, ताकि राजधानीवासियों को वास्तविक राहत मिल सके।

बैज बोले- प्रदेश में अपराधी बेखौफ और बेलगाम

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, जांजगीर-चांपा के जैजैपुर में एक व्यवसायी के घर में घुस कर गोली मारे जाने की घटना बेहद ही चिंता का विषय है। यह घटना राज्य की बिगड़ चुकी कानून व्यवस्था का एक और उदाहरण है। जांजगीर-चांपा में व्यवसायी के घर में अपराधियों ने उनके बड़े बेटे की गोली मार कर हत्या कर दी, छोटा बेटा घायल है। अब आदमी अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। अपराधी इतने बेखौफ और बेलगाम हो चुके हैं कि उनमें कानून का जरा भी भय नहीं बचा है।

श्री बैज ने कहा, जांजगीर की घटना के पहले प्रदेश में गैंगवार की अनेक घटनाएं पिछले ढाई साल में हुई हैं। राजधानी में पांच बार गोलियां चलाई गईं, रायपुर सेंट्रल जेल के सामने गोलियां चलाई गईं, झारखंड के गैंगस्टर रायपुर में गोलीबारी कर चुके हैं, बिलासपुर के मस्तूरी में व्यवसायी के ऊपर गोलियां चलाई गईं। अब तो घर में घुस कर गोली मारी जा रही है। श्री बैज ने कहा, साय सरकार में छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है। लूट, हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार की घटनाओं के आंकड़े बताते हैं कि राज्य की कानून व्यवस्था बदतर हो चुकी है। हर घटना के बाद सरकार और पुलिस का एक रटा रटाया बयान आता है कि दोषी बख्शे नहीं जाएंगे।

भाजपा बोली- कांग्रेस शासन में अपराधियों का ठिकाना बन गया था मुख्यमंत्री निवास

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. विजय शंकर मिश्रा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के बयानों को कोरी सियासत करार देते हुए उन पर कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा, कांग्रेस के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में अपराध की स्थिति इतनी भयावह थी कि आम नागरिक घर से बाहर निकलने पर अपनी सुरक्षा को लेकर हर पल सशंकित रहता था। कांग्रेस शासन में मुख्यमंत्री निवास ही अपराधियों का ठिकाना बन गया था। डॉ. मिश्रा ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा, कांग्रेस सरकार के दौरान मुख्यमंत्री निवास से शराब से लेकर सट्टा तक का अवैध कारोबार संचालित होता था। उस समय तत्कालीन मुख्यमंत्री का आवास एक तरह से अपराधियों का नया ठिकाना बन गया था, यह बात किसी से छिपी नहीं है।

विधानसभा के विशेष सत्र में शामिल होगा विपक्ष, तय होगी रणनीति

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र में विपक्ष शामिल होगा। हालांकि इससे पहले कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी या नहीं, अभी तय नहीं हो पाया है। माना जा रहा है कि एक दिन पहले विधायक दल औपचारिक रणनीति तय करने जुट सकता है। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने स्पष्ट कर दिया है कि सत्र में शासकीय कार्य संपादित किए जाने की जानकारी दी गई है, इसलिए विपक्ष कार्यवाही में भाग लेगा। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा निंदा प्रस्ताव लाने से संबंधित दिए गए बयान को लेकर भी कटाक्ष किए। वहीं सवाल भी उठाए कि क्या किसी अन्य सदन में हुई चर्चा को लेकर इस सदन में चर्चा हो सकती है। विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर विपक्ष की रणनीति क्या होगी, अभी तय नहीं किया गया है। सूत्रों के मुताबिक नेता प्रतिपक्ष ने इस मामले में दिल्ली में भी वरिष्ठ नेताओं से चर्चा की है। इधर एक दिन के सत्र को लेकर सभी विधायकों को अलग निर्देश भी दिए जाएंगे। हालांकि यह स्पष्ट कर दिया गया है कि विपक्ष सत्र में शामिल होगा और चर्चा भी करेगा। सत्र की अधिसूचना में शासकीय कार्य संचालित किए जाने का जिक्र किया गया है। विपक्ष ने इस वजह से सत्र में शामिल होने पर सहमति जताई है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष ने पूर्व में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा निंदा प्रस्ताव लाने के बयान को लेकर भी निशाना साधा है। वहीं सवाल उठाया कि क्या यह संवैधानिक है? गौरतलब है कि अधिसूचना जारी होने से पहले नेता प्रतिपक्ष ने दो दिनों के विशेष सत्र की मांग उठाई थी। उन्होंने कहा था कि विपक्ष को भी अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत ने कहा कि शासकीय कार्य है तो विपक्ष कार्यवाही में भाग लेगा और पूरा सहयोग भी करेगा। उन्होंने सवाल उठाए कि मुख्यमंत्री ने पहले निंदा प्रस्ताव लाने को लेकर बयान दिया था। आखिर किस अनुभवहीन सलाहकार ने उन्हें सलाह दे दी। क्या लोकसभा की कार्यवाही के खिलाफ यहां चर्चा कराएंगे। किसी अन्य सदन में हुई चर्चा पर यहां कैसे चर्चा कर सकते हैं। यह संवैधानिक नहीं है।

आप भाजपा की बी-टीम, जहां से निकले वहीं लौट रहे : भूपेश

रायपुर। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा समेत सात सांसदों के भाजपा में शामिल होने पर कटाक्ष किए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम है। अब उनके लोग अपनी ओरिजनल पार्टी में जा रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल विवेकानंद फाउंडेशन में बैठने वाले लोग हैं। इस फाउंडेशन में रामदेव बाबा भी बैठे। अन्य लोग भी यहां बैठे और आंदोलन की शुरुआत की। आम आदमी पार्टी भी वहीं से निकली है। ये भाजपा की बी टीम है। अब वो अपनी ओरिजनल पार्टी में वापस हो रहे हैं। ये सब लोग वहीं से निकले हैं। आम आदमी पार्टी और भाजपा में कोई अंतर नहीं है। ये सब अपनी मुख्यधारा में वापस हो रहे हैं। अब देखना बस ये है कि केजरीवाल कब भाजपा में जाते हैं।

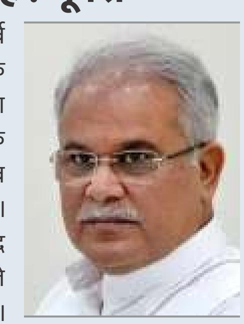

बैज की चिंताएं व्यर्थ व राजनीति से प्रेरित : डॉ. मिश्रा

रायपुर। भाजपा प्रवक्ता डॉ. निनवाशंकर मिश्रा ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के कानून व्यवस्था से जुड़े सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी चिंताएं पूरी तरह व्यर्थ और राजनीति से प्रेरित हैं। उन्होंने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा कि भाजपा की जब भी राज्य में सरकार रही है अपराध पर अंकुश लगाने का ही काम किया है। आलम यह है कि रायपुर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद अब अन्य जिलों से भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली की मांग आ रही है। उन्होंने कहा कि श्री बैज को कांग्रेस शासनकाल का वह दौर नहीं भूलना चाहिए, जब छत्तीसगढ़ में एफआईआर तक दर्ज नहीं होती थी। मुख्यमंत्री निवास से शराब से लेकर सट्टा तक के अवैध कारोबार को संरक्षण दिया जाता था। जब कांग्रेस शासनकाल में अपराध चरम पर था, तब श्री बैज मौन थे? जबकि आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में अपराध पर त्वरित कार्रवाई हो रही है और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिल रही है। डॉ. मिश्रा ने कहा कि भाजपा सरकार ने ही छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नक्सलवाद की समस्या का निराकरण किया है, यह बात किसी से छिपी नहीं है। इससे कांग्रेस के नेता हताश और निराश हैं, इसलिए अनर्गल बयानबाजी करते हैं, जिसका जनमानस से कोई सरोकार नहीं होता है।

घर में घुसकर गोली मार रहे, गृहमंत्री पॉलिटिकल टूरिज्म पर : कांग्रेस

रायपुर। जांजगीर चांपा जिले के जैजैपुर में व्यवसायी के घर में घुसकर गोली मारने की घटना के बाद कांग्रेस ने फिर राज्य की बदहाल कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। यही आरोप लगाए कि ये घटना बदहाल हालातों का उदाहरण है। इसकी जवाबदेही कौन लेगा? अब लोग अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। बेखौफ अपराधियों में कानून का भय खत्म हो गया है। इधर प्रदेश के गृह मंत्री पॉलिटिकल टूरिज्म पर हैं। मुख्यमंत्री को सरकार से मतलब नहीं, गृहमंत्री चुनाव प्रचार और रैलियों में मस्त हैं। आम लोग खौफ में जी रहे हैं। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने आरोप लगाए कि अपराधगढ़ बन चुके छत्तीसगढ़ में लूट, हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार की घटनाओं के आंकड़े ही बदतर कानून व्यवस्था को बताते हैं। घटना का कोई दोहराव न हो, इसके लिए सरकार और पुलिस के पास कोई ठोस कार्ययोजना नहीं है। कानून व्यवस्था सरकार की लापरवाही, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की अक्षमता के कारण बिगड़ी है। प्रदेश में हर दिन 8 बलात्कार और हर दूसरे दिन 3 सामूहिक दुराचार की घटनाएं हो रही हैं।

नक्सलमुक्त बस्तर में अब हो रहे हैं तेजी से निर्माण कार्य

रायपुर। नक्सलमुक्त आबूझमाड़ क्षेत्र में अब निर्माण कार्य तेजी से किये जा रहें। क्षेत्र में सड़क, जल निकासी, ओवरहेड टैंक, लघु सिंचाई योजना सहित अन्य अधोसंरचनाओं के कार्यो ने जोर पकड़ लिया है पिछले दिनों नक्सलमुक्त आबूझमाड़ में सीटीई की टीम ने विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया।

टीम ने नारयणपुर के हरिमार्कटोला, सड़क का निरीक्षण किया। टीम ने देखा कि निर्मित सड़कों मोटाई और चौड़ाई को सही मानक स्तर की है, इसी तरह ग्राम ओरछा ब्लाक में निर्मित शेड की निरीक्षण किया गया । जिले के ग्राम पालकी में निर्मित ओवरहेड टैंक की टीम ने निरीक्षण किया। इसी तरह से जल निर्माण संसाधन विभाग के अंतर्गत बैनूर रिजर्वायरके नवीनीकरण कार्य का निरीक्षण किया गया। टीम ने उपस्थित अधिकारियों से निर्माण कार्यों की विस्तार से जानकारी ली एवं अधिकारियों को जरूरी मार्गदर्शन भी दिया। नक्सलमुक्त बस्तर में अब विभिन्न निर्माण कार्यों के निरीक्षण करने जांच एजेन्सीयों के दल आसानी से पहुंच रहे हैं। तकनीकी टीमों द्वारा निर्माण कार्यों को कराने स्थानिय अधिकारियों को उचित मार्गदर्शन भी दिया जा रहा है, जिससे अब अबूझमाड़ में निर्माण कार्य तेजी से किए जाने लगे हैं।

एक लाख की इनामी महिला नक्सली ने किया आत्मसमर्पण

मोहला। मोहला- मानपुर- अंबागढ़ चौकी में एक लाख रुपए की ईनामी महिला नक्सली ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में लौटने का फैसला लिया है। पुलिस के अनुसार जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रयास, शासन की पुनर्वास नीति तथा पुलिस द्वारा लगातार किए जा रहे जनसंपर्क अभियान से प्रभावित होकर उक्त महिला नक्सली देहकी उर्फ जीत्ती सदस्या रावघाट ने मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया। संगठन के विचारों से मोहभंग, अंदरूनी मतभेद, संगठन में उपेक्षा तथा ग्रामीणों पर किए जा रहे अत्याचार से परेशान होकर उसने आत्मसमर्पण किया। यह कार्रवाई पुलिस महानिरीक्षक बालाजी राव सोमावर के मार्गदर्शन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वायपी सिंह के निर्देशन में की गई। पुलिस के मुताबिक वर्ष 2010 में संगठन से प्रभावित होकर माओवादी संगठन में शामिल हुई।

वेदांता हादसा, मृतकों का आंकड़ा पहुंचा 25

रायपुर। सक्ती जिले के सिंघीतराई स्थित वेदांता थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर फटने से हुए भीषण हादसे में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रायपुर अस्पताल में भर्ती एक और श्रमिक की मौत के बाद इस हादसे में मरने वालों की संख्या 25 जा पहुंची है। गुरुवार 23 अप्रैल की रात्रि में रायपुर में भर्ती घायल श्रमिक विश्वजीत साहू की मौत हो गई। वेदांता पॉवर प्लांट में हुए हादसे के बाद की गई एफआईआर की कॉपी देखने के लिए युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष साथियों सहित डभरा थाना में धरने पर बैठे रहे और घंटों एफआईआर की कॉपी की मांग करते रहे। वेदांता पावर प्लांट में हुए बॉयलर हादसे में 25 मजदूरों की मौत और आधा दर्जन से अधिक के गंभीर रूप से घायल होने के मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को नोटिस जारी किया है।

योजनाओं को वीडियो पोस्ट व समाचारों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं : सीपीआरओ

- जनसंपर्क का कार्य जिम्मेदारी का, इसे गंभीरता से लें, परिणाम के अनुसार होगा अधिकारियों का मूल्यांकन

रायपुर।जनसंपर्क आयुक्त रजत बंसल ने शुक्रवार को नवा रायपुर स्थित संवाद कार्यालय में जनसंपर्क संचालनालय और जिला जनसंपर्क अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि वर्तमान दौर में जनसंपर्क अधिकारियों को न्यू एज मीडिया की सभी विधाओं में दक्ष होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि बदलते समय के साथ तकनीक और संचार के माध्यमों को अपनाना ही प्रभावी जनसंपर्क की कुंजी है। जनसंपर्क आयुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा कि जनसंपर्क का कार्य अत्यंत जिम्मेदारीपूर्ण है, इसलिए इसे पूरी गंभीरता के साथ किया जाना चाहिए और किसी भी प्रकार की कोताही से बचना जरूरी है। जनसंपर्क अधिकारी शासन और जनता के बीच सेतु की भूमिका निभाते हैं, ऐसे में उनकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि परिणाम के अनुरूप हर अधिकारी के कार्य का मूल्यांकन किया जाएगा। जनसंपर्क आयुक्त ने आगामी एक मई से शुरू हो रहे प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के प्रचार-प्रसार की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का अधिकतम उपयोग किया जाए। जनसंपर्क आयुक्त ने इस बात पर विशेष रूप से जोर दिया कि राज्य में हो रहे विकास कार्यों और योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों के वास्तविक अनुभवों को वीडियो पोस्ट और समाचारों के माध्यम से जन-जन तक पहुंचाया जाए। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया के साथ सतत संपर्क और समन्वय बनाए रखा जाए।

जापान के प्रतिनिधिमंडल से मिले सीएम निवेश, तकनीकी सहयोग पर हुई चर्चा

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में जापान से आए प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रतिनिधिमंडल का आत्मीय स्वागत करते हुए छत्तीसगढ़ में निवेश की संभावनाओं, औद्योगिक विकास और तकनीकी सहयोग के विभिन्न आयामों पर विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री साय ने इस अवसर पर अपने जापान प्रवास का उल्लेख करते हुए कहा कि राज्य सरकार की उद्योगोन्मुखी और निवेश प्रोत्साहनकारी नीतियों के कारण छत्तीसगढ़ वैश्विक निवेशकों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि जापान तकनीकी दृष्टि से अग्रणी देश है और वहां की उन्नत विशेषज्ञता का लाभ छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। मुख्यमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि इस प्रकार के निवेश और सहयोग से प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा राज्य के औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी। जापान से आए प्रतिनिधिमंडल ने छत्तीसगढ़ सरकार की नई औद्योगिक नीति की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में निवेश के लिए अनुकूल और पारदर्शी वातावरण तैयार हुआ है, जिससे उद्योगों के विस्तार के लिए बेहतर संभावनाएं उपलब्ध हो रही हैं।

वर्षों तक अंधेरे में जीवन गुजारने वाले ग्रामीणों के घरों में पहली बार बल्ब जले

दशकों का अंधेरा टूटा, अबूझमाड़ के ईरपानार गांव में पहली बार पहुंची बिजली

रायपुर। कभी नक्शे पर नाम भर रह गया ईरपानार आज उम्मीदों की नई पहचान बन गया है। अबूझमाड़ के गहरे जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और दुर्गम पगडंडियों के बीच बसे इस छोटे से गांव में पहली बार बिजली पहुँची है। वर्षों तक अंधेरे में जीवन गुजारने वाले ग्रामीणों के घरों में जब पहली बार बल्ब जले, तो गांव ने सिर्फ उजाला नहीं देखा, बल्कि विकास को महसूस किया।

ईरपानार नारायणपुर जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है, लेकिन यह दूरी सामान्य रास्ते जैसी नहीं है। यहां तक पहुंचने के लिए कच्चे मार्ग, पहाड़ी चढ़ाई, घने वन क्षेत्र और कई स्थानों पर पैदल सफर करना पड़ता है। बरसात के मौसम में संपर्क और भी कठिन हो जाता है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, नारायणपुर संभाग ने इस चुनौतीपूर्ण कार्य को प्राथमिकता से पूरा किया। कार्यपालन अभियंता सहित विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद मिशन मोड में काम कर सफलता हासिल की। कलेक्टर नम्रता जैन ने बताया कि ईरपानार तक बिजली पहुंचाना सामान्य तकनीकी कार्य नहीं था। कई हिस्सों में बिजली खंभे, तार और सामग्री पहुंचाने के लिए कठिन श्रम करना पड़ा। टीम को

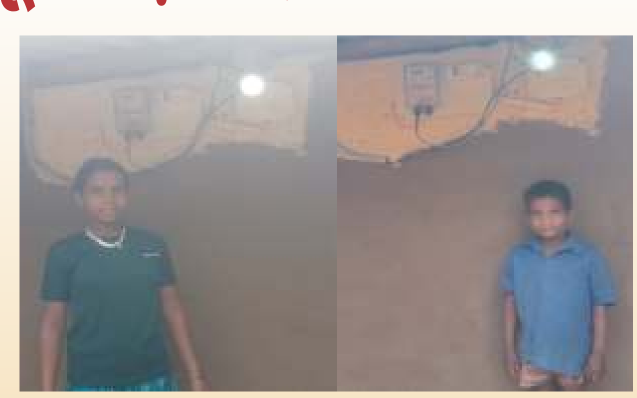

ऊबड़-खाबड़ पहाड़ी रास्तों, जंगलों और सीमित संसाधनों के बीच काम करना पड़ा। कई स्थानों पर मशीनों की बजाय मानव श्रम और स्थानीय सहयोग से सामग्री पहुंचाई गई। बिजली लाइन विस्तार, पोल स्थापना और कनेक्शन कार्य को समयबद्ध तरीके से पूरा कर विभागीय टीम ने मिसाल पेश की है।

₹56.11 लाख की लागत, लेकिन असर पीढ़ियों तक

ग्राम ईरपानार के विद्युतीकरण कार्य पर कुल ₹56.11 लाख की लागत आई। इस परियोजना के तहत गांव के परिवारों को पहली बार विद्युत कनेक्शन प्रदान किया गया , एवं उस सोच का प्रतीक है जिसमें अंतिम छोर पर बसे परिवार को भी विकास का समान अधिकार दिया जा रहा है।

अब बच्चों के सपनों को मिलेगा उजाला

बिजली आने से अब गांव के बच्चों को रात में पढ़ाई के लिए रोशनी मिलेगी। मोबाइल चार्जिंग जैसी सामान्य सुविधा, जो शहरों में सहज है, अब यहां भी उपलब्ध होगी। पंखे, लाइट और छोटे घरेलू उपकरणों से जीवन आसान होगा। भविष्य में डिजिटल शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, संचार सुविधाओं और छोटे व्यवसायों के अवसर भी विकसित हो सकते हैं। जब पहली बार गांव में बल्ब जले, तो बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर चेहरे पर उत्साह दिखाई दिया। कई ग्रामीणों ने कहा कि उन्होंने अपने घरों में पहली बार स्थायी रोशनी देखी है। वर्षों से लालटेन, लकड़ी और सीमित साधनों पर निर्भर जीवन अब बदलने लगा है।

113 साल पहले आई सिनेमा की पहली हीरोइन

समाज से हुआ बहिष्कार, ऐसे खत्म किया मर्दों का 'साड़ी' वाला दौर!

भारतीय सिनेमा को बिना किसी एक्ट्रेस के शायद कभी आपने सोचा भी नहीं होगा? लेकिन जब भारत में फिल्में बनना शुरू हुई तो एक्टिंग के प्रोफेशन को महिलाओं के लिए सम्मानजनक नहीं माना जाता है और इसीलिए भारत की पहली फिल्म राजा हरिशचंद्र में कोई महिला एक्ट्रेस थी ही नहीं। राजा हरिशचंद्र में पुरुषों ने ही महिलाओं के किरदार निभाए थे। लेकिन भारतीय सिनेमा के जनक दादासाहेब फाल्के ने ही इस प्रथा को तोड़ा और उसी साल अपनी दूसरी फिल्म मोहिनी भस्मासुर में दुर्गाबाई कामत को ब्रेक दिया।

उन्होंने फिल्म में पार्वती नाम का लीड किरदार निभाया था। इतना ही नहीं इस फिल्म से उनकी बेटी ने भी इस फिल्म से बतौर चाइल्ड एक्टर डेब्यू करते हुए मोहिनी का किरदार निभाया। दुर्गाबाई कामत (1879) मराठी फिल्मों की एक भारतीय अभिनेत्री थीं, जो भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री बनीं। उन्हें भारतीय सिनेमा की 'पहली महिला अभिनेत्री' के रूप में जाना जाता है, उस समय, जब प्रतिष्ठित परिवारों की लड़कियों के लिए अभिनय को एक उचित पेशा नहीं माना जाता था। भारतीय सिनेमा की पहली हीरोइन दुर्गाबाई कामत बहुत कम जानी-मानी फिल्मों में नजर आईं। मोहिनी भस्मासुर के अलावा उनकी 'बाबंची बायको' (1927) और 'गुलामी जंजीर' (1931) प्रमुख फिल्मों में शामिल हैं। 'मोहिनी भस्मासुर' 1913 की एक भारतीय पौराणिक (Mythological) फिल्म है, जिसका निर्देशन दादासाहेब फाल्के (Dadasaheb Phalke) ने किया था और इसमें कमलाबाई गोखले और दुर्गाबाई कामत ने मुख्य भूमिकाएं निभाई थीं। यह भारत और फाल्के की दूसरी फुल लेंथ फीचर फिल्म है। 'मोहिनी भस्मासुर' पहली ऐसी भारतीय फिल्म है जिसमें किसी महिला अभिनेत्री ने अभिनय किया था। भारत और फाल्के की पहली फिल्म 'राजा हरिश्चंद्र' में, महिला की भूमिका एक पुरुष, अन्ना सालुंके ने निभाई थी। दुर्गाबाई कामत ने समाज की बेड़ियों को तोड़कर आगे की पीढियों के लिए भारतीय सिनेमा में जगह बनाई वहीं इसका श्रेय दादासाहेब फाल्के को भी जाता है। जिन्होंने समाज की परवाह किए बिना महिलाओं के लिए एक बड़ा कदम उठाया।

33 साल बाद 'खलनायक' बनकर लौटे संजय दत्त

1993 की सुपरहिट फिल्म खलनायक की यादें आज भी दर्शकों के दिलों में जिंदा हैं. संजय दत्त, माधुरी दीक्षित की इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ाया था. अब 33 साल बाद खलनायक फिर से लौटने वाला है. अपना दिल थामकर रखिए क्योंकि खलनायक रिटर्न्स का धमाकेदार आगाज हो गया है. संजत दत्त सालों बाद फिर से खलनायक बनकर लौटे हैं. मूवी का फर्स्ट लुक अनाउंसमेंट वीडियो सामने आया है. वीडियो का पहला ही सीन खौफनाक है. खून-खराबा दिखाया गया है. चारों तरफ आग लगी हुई है. हर ओर लाशें बिछी हैं. तभी खून से लथपथ एक शख्स के सामने संजय दत्त आकर बैठते हैं. एक्टर के चेहरे पर चोट के निशान हैं. खून निकल रहा है. वो टशन में अपनी सिगार जलाते हैं. टीजर में संजय दत्त का खूंखार अंदाज दिखा है. लंबे बाल, दाढ़ी में उनका इंटेंस लुक खौफ पैदा करता है. उनके सामने पड़ा शख्स जान की भीख मांग रहा है. उससे संजय कहते हैं- बोला था ना, रात के 10 बजे बल्लू जेल से फुररररर... नायक नहीं खलनायक हूं मैं. संजय दत्त का स्वैग दमदार है. उनका किलर लुक देख फैंस क्रेजी हो रहे हैं. संजय दत्त ने ये टीजर शेयर करते हुए लिखा- कुछ कहानी खत्म नहीं होती.... वो दोबारा शुरू होती है. खलनायक रिटर्न्स. फिल्म में संजय के अलावा बाकी किरदारों की कास्टिंग का अभी खुलासा नहीं हुआ है. फैंस का ये टीजर देखकर कहना है- ये हुआ ना असली लेजेंड का कमबैक.

रिहाना ने आफ्टर पार्टी में ईशा और जाह्नवी संग मचाया धमाल

ग्लोबल आइकन रिहाना इस वक्त मुंबई में हैं. करीब दो साल बाद वो एक ब्यूटी इवेंट में हिस्सा लेने के सिलसिले में भारत लौटी हैं. फेंटी ब्यूटी के लॉन्च इवेंट का आयोजन बीती रात मुंबई में हुआ, जहां रिहाना का ग्लैमरस अंदाज देखने को मिला. इस इवेंट में कई सेलेब्स भी पहुंचे. अब ओरहान अवात्रामणि उर्फ ओरी ने रिहाना की आफ्टर पार्टी का एक वीडियो शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

ओरी ने इंस्टाग्राम पर एक रील शेयर की है, जिसमें रिहाना, ईशा अंबानी और जाह्नवी कपूर धमाल मचाती दिख रही हैं. वीडियो में डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की झलक दिख रही है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'अबाउट लास्ट नाइट. ईशा अंबानी ने रिहाना के लिए एक आफ्टर पार्टी का आयोजन किया था. वीआईपी टेबल से एक खास झलक.'

रिहाना से बातचीत करते दिखे ओरी

ओरी ने एक और वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है, जिसमें वो और रिहाना चिटचैट करते दिख रहे हैं. दोनों के बीच कान की बालियों के लेकर कुछ बातचीत चल रही है. ओरी ने कैप्शन लिखा है, 'फिर से मुलाकात हुई. वो उन बालियों को लौटाने के अलावा और सब कुछ कर रही हैं.' इसके अलावा ओरी का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वो और रिहाना पैपराजी को पोज देते दिख रहे हैं. इस दौरान ओरी अपना सिग्नेचर पोज देना नहीं भूले, जिसमें वो अक्सर बॉलीवुड सेलेब्स के साथ भी फोटोज क्लिक कराते हैं.

रिहाना से पहले भी मिल चुके हैं ओरी

बता दें कि रिहाना इससे पहले साल 2024 में अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के जामनगर में आयोजित तीन दिवसीय प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन में शामिल होने भारत आई थीं. उन्होंने वहां जबरदस्त परफॉर्म भी किया था. तब भी ओरी के साथ उनकी काफी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिली थी.

अमीषा पटेल को 'तेरे नाम' ठुकराने का सालों बाद हुआ पछतावा

90s की टॉप एक्ट्रेस अमीषा पटेल आज भले ही स्क्रीन पर कम नजर आती हैं लेकिन एक समय था जब उन्होंने गुजरे दौर में 'गदर 2' और 'हमराज' जैसी हिट फिल्मों में काम किया. अभिनेत्री ने ऋतिक रोशन के साथ फिल्म 'कहो ना प्यार है' से डेब्यू किया था. अमीषा पटेल के बारे में बहुत कम ही लोगों को पता होगा कि उन्हें सलमान खान की 'तेरे नाम' भी ऑफर हुई थी और एक्टर उनके साथ ये फिल्म करने के लिए बहुत एक्साइटेड थे. ऐसा हम नहीं बल्कि अमीषा का कहना है. सालों बाद उन्हें ये फिल्म ठुकराने का पछतावा हुआ है. दरअसल, अमीषा पटेल ने हाल ही में बॉलीवुड बबल को दिए इंटरव्यू में काफी कुछ शेयर किया. अभिनेत्री ने अपनी डेब्यू फिल्म से लेकर करियर में आए उतार-चढ़ाव और अनिल शर्मा के साथ क्रिएटिव डिफ्रेंसेस पर बात की. इसी बीच उनसे सलमान खान की हिट फिल्म 'तेरे नाम' को ठुकराने को लेकर भी सवाल किया गया था तो अभिनेत्री ने इस पर पछतावा जाहिर किया.

क्यों नहीं की सलमान खान की 'तेरे नाम'?

इस बातचीत में अभिनेत्री ने कहा, 'काश मैं मना नहीं करती. उस समय जब सलमान ने मुझे ये फिल्म ऑफर की थी. सिर्फ गाने बन चुके थे और ये फिल्म का आइडिया और कहानी थी. उन्होंने मुझे नैरेट किया, गाने भी सुनाए. तब तक ना तो डेट्स फिक्स थी और ना ही ये तय था कि कौन डायरेक्ट करेगा. सब कुछ हवा में था. सलमान खान इसके लिए काफी एक्साइटेड थे. जब चीजें फाइनल हुईं और सतीश कौशिक ऑनबोर्ड हुए. सब कुछ हुआ और तब तक मैं किसी और प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो गई थी. सतीश कौशिक से पहले कई लोगों के नाम सामने आए थे कि ये डायरेक्ट करेंगे वो करेंगे. कुछ सेट नहीं था.'

भूत बंगला ने दुनियाभर में कमाए 100 करोड़

अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की सुपरहिट जोड़ी का जादू एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर सर चढ़कर बोल रहा है. उनकी लेटेस्ट हॉरर-कॉमेडी 'भूत बंगला' ने सिनेमाघरों में अपना पहला हफ्ता शानदार तरीके से पूरा कर लिया है. तब्बू और वामीका गब्बी जैसे सितारों से सजी इस फिल्म ने सातवें दिन भी अपनी पकड़ मजबूत बनाए रखी और 84 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. बड़े बजट की फिल्मों से कड़ी टक्कर मिलने के बावजूद यह फिल्म दर्शकों को खींचने में कामयाब रही है. हॉरर कॉमेडी मूवी की रिलीज को एक हफ्ता हो गया, लेकिन अभी तक यह भारत में 100 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है. हालांकि, 'भूत बंगला' ने वर्ल्डवाइड सिर्फ तीन दिनों में ही 100 करोड़ रुपये कमा लिए थे.

अंग्रेजों के सामने न झुके न टूटे-गुंडाधूर

सुधीर सक्सेना

भूमकाल प्रसंग का महत्वपूर्ण ग्राम उलनार जगदलपुर तहसील के अंतर्गत पूर्वी बस्तर का एक ग्राम है। यहां 'भतरी' बोली जाती है। उलनार में ही हथियार इकट्ठे किए गए। क्रांति की शपथ ली गई और यहीं से माड़िया धुरवा क्रांतिकारी भत्ता बांध कर, लाल मिर्च बंधी आम की टहनियां लेकर प्रचार हेतु निकल पड़ते थे।

डारा मिर्च देखकर अन्य वनवासी भी भूमकाल में सम्मिलित हुए। गुंडाधूर धुर आदिवासी था। बस्तर ही उसकी दुनिया थी। स्कूल कभी गया नहीं। जीवन में शायद ही कभी केशकाल घाटी के नीचे उतरा हो। बावजूद इन सबके उसका चरित्र खांटी सात्विक है। अपने समय के वीरों में आपकी नीति बिल्कुल ही अलग रही। उन्होंने न तो हथियार डाले, न अंग्रेजों के हाथ लगे, और न ही समर्पण किए। गुंडाधूर एक महानायक हैं क्योंकि वह अविचारित शक्तियों का भंडार है, जो आदिम शक्तियों का भंडार है, जो आदिम परिवेश में एक महानायक के लिए अपरिहार्य हैं। गुंडाधूर और लाल साहब में प्रगाढ़ मैत्री थी। दोनों गजामुंग मितान और सिरहा थे। जगदलपुर में मूरतसिंह बख्शी की हवेली में अक्सर बैठकें हुआ करती थीं। गुंडाधूर की क्रांति प्रतिभा यहीं सक्रिय हुई।

सुंदर विचार वाले लोगों का गांव है सुंदरा

पवन यादव 'पहुना'

जननी और जन्मभूमि मनुष्य के लिए कभी भुला देने वाली स्थान नहीं होता। गांव का नाम सुंदरा पड़ा, इस पर गंभीरता से गांव के बुजुर्गों व बुद्धिजीवियों से चर्चा करने पर कई कारण गांव के नाम के पीछे कारण बताते हैं। जिसके पीछे महत्वपूर्ण कारण यह है कि इस गांव में पहले कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होते थे, गांव के लोग मिल जुलकर रहते थे तथा गांव के किसी समस्या आने पर बिना भेदभाव के निपटा लेते थे। कोर्ट कचहरी को तो न देखे न जानते थे। आसपास के गांव के लोग सुंदरा गांव की तारीफ किया करते थे। सभी सुंदर विचार वाले लोगों का गांव होने के कारण गांव का नाम रखा गया सुंदरा।

गांव राजनांदगांव से 5 किलोमीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग से लगा हुआ है। गांव में बहुत पुराना रामायण समिति है जो 1946 में गठित हुआ है। प्राथमिक पाठशाला का निर्माण 1956 में हुआ है जिसका उद्घाटन मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल माननीय डॉ. पट्टाभि सीतारमैय्या के कर कमलों द्वारा किया गया। अजय नाथ बाबा का आश्रम, माता अन्नपूर्णा देवी मंदिर, हनुमान जी का मंदिर है। गांव से लगा हुआ प्रसिद्ध कबीर आश्रम है। गांव में सड़क किनारे प्रसिद्ध दंत चिकित्सा महाविद्यालय और चिकित्सालय है।

भूकंप के कारण नष्ट होने का अनुमान

सिरपुर के सुरंग टीला मंदिर

ललित शर्मा

देखने में आता है कि भूकंप आने पर बड़े बड़े नगर और राजधानी कुछ पलों में धरती में समा जाती हैं। धरती का एक बार थरथराना ही हजारों लाखों लोगों को काल के आगोश में समा देने के लिए काफी होता है। श्रीपुर के पतन में भूकंप की भूमिका भी रही होगी। भूकंप के चिन्ह सुरंग टीला स्थित पंचायत मंदिर के अधिष्ठान अधिष्ठान में दिखाई देती है। देखा जाए तो सुरंग टीला मंदिर की जगती भारत के मंदिरों में सबसे अधिक ऊंचाई पर है। मुख्य मंदिर तक पहुंचने के लिए 43 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। इसका तल विन्यास नदी के तल से 17 फुट ऊंचा है। वर्तमान में मंदिर की सीढ़ियां दबी हुई है। इनके कोण बदले हुए हैं। विशाल मंदिर की संरचना में परिवर्तन सिर्फ भूकंप से ही आ सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि श्रीपुर या सिरपुर में भूकंप भी आया होगा, जिसके कारण यह नगर ढह गया होगा।

विकास की दशा और दिशा बदली राजा साहब शिव मंगल सिंह ने

डॉ रामचंद्र सिंहदेव

सन 1900 में राजा साहब शिवमंगल सिंह ने अपनी राजधानी को सोनहत से बैकुंठपुर में स्थानांतरित कर दिया। बैकुंठपुर लगभग कोरिया रियासत के केंद्र बिंदु में था। इस कारण वहां से समस्त राज्य का प्रशासन बेहतर ढंग से किया जा सकता था। उन्होंने दो तालाब एवं एक मंदिर का निर्माण कराया जो नए महल के निकट स्थित है। इनके परिवार की बहन बाई देव कुंवर में मनुष्यों की प्रकृति को पहचानने की अद्भुत प्रतिभा थी। इसके साथ साथ वे ज्योतिष शास्त्र में निपुण होने के साथ ही कूट राजनीतिज्ञ भी थी। राजा साहब ने उन्हें तृतीय श्रेणी दंडाधिकारी के समस्त अधिकार प्रदान किए। वे प्रशासनिक कार्यों में राजा साहब की सहायता करती थी। वे अत्यंत धार्मिक एवं दानशील स्वभाव की महिला थी, जो सदैव गरीबों की समस्याओं का अध्ययन कर अपनी सामर्थ्य अनुसार उनकी सहायता किया करती थी। समाज के लोग उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। उन्हें स्नेहपूर्वक बाई साहब कह कर सम्बोधित किया जाता था। बैकुंठपुर में बाई साहब के नाम से एक तालाब खुदवा कर उसका नाम बाई सागर रखा गया। सन 1906 में उनका स्वर्गवास हो गया।

पति और पत्नी के वैवाहिक जीवन में विच्छेदन होने को कहा जाता है : छाड़रा छाड़ी

एम. एस. पैकरा

छत्तीसगढ़ अंचल में छाड़रा छाड़ी शब्द जशपुर - सरगुजा की स्थानीय बोली के आधार पर कहा जाता है। जब पति और पत्नी के बीच आपसी सामंजस्य नहीं बैठ पाने पर दोनों में विचारों में मतभेद के कारण, पति अथवा पत्नी द्वारा एक दूसरे को प्रताड़ित करने के कारण दोनों के बीच सम्बन्ध टूट जाता है, और पत्नी अपने पति से अलग होकर अपने मायके चली जाती है। ऐसे समस्या को सामाजिक नियमानुसार हल किया जाता है। यदि सामाजिक व्यवस्था में कोई निर्णय को मानते नहीं तो दंड लेकर अलग रहने के लिए मान्य किया जाता है जिसे छाड़रा छाड़ी कहा जाता है। इस निर्णय के बाद पत्नी को अपने पूर्व पति के संपत्ति में हक पाने का अधिकार नहीं रहता। आगे दोनों पति पत्नी अब अपने अनुसार दूसरी कर सकते हैं।

मुख्य संवाददाता/प्रदीप चंद्रवंशी
मोबाईल नंबर 7000681023

नशे का 'नेशनल कॉरिडोर' अब तस्करों के लिए 'डेथ वारंट'

सफेदपोश सौदागरों पर 'वज्रपात': ट्रांजिट हब से 'जस्टिस हब' बनता छत्तीसगढ़

शहर सत्ता/ रायपुर। छत्तीसगढ़ की भौगोलिक स्थिति इसे देश के ड्रग मैप पर एक संवेदनशील केंद्र बना रही है। एक तरफ ओडिशा की सीमाओं से घुसता गांजे का अथाह भंडार है, तो दूसरी तरफ पुलिस और न्यायपालिका का वो 'चक्रव्यूह', जिसमें अब बड़े-बड़े तस्कर फंस रहे हैं। यह सिर्फ तस्करी की खबर नहीं है, बल्कि राज्य के भविष्य को नशे की दीमक से बचाने की सबसे बड़ी कानूनी जंग है।

भाग 1: 'ब्लैक कॉरिडोर'—NH-53 पर मौत का सामान

छत्तीसगढ़ का उपयोग अब केवल उपभोग के लिए नहीं, बल्कि 'नेशनल ट्रांजिट हब' के रूप में हो रहा है। ओडिशा से उठने वाली नशे की खेप छत्तीसगढ़ के रास्तों से होकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड तक पहुंच रही है।

तस्करी के शातिर 'मॉडस ऑपरेंडी'

पुलिस की सख़्ती बढ़ी तो तस्करों ने अपने तरीके और भी शातिर कर लिए हैं:

सब्जियों का कवच: महासमुंद में हाल ही में पकड़े गए 912 किलो गांजे (कीमत ₹4.56 करोड़) को केले के गुच्छों के नीचे बेहद सावधानी से छिपाया गया था।

गुप्त चैंबर और हाईटेक गाड़ियां: लग्जरी कारों की डिक्की, ट्रकों की छतों और डीजल टैंकों के बीच गुप्त चैंबर बनाकर करोड़ों का माल पार किया जा रहा है।

डिजिटल रूट: अब बड़ी खेप के साथ-साथ कूरियर और सोशल मीडिया के जरिए 'माइक्रो-स्मगलिंग' का नया ट्रेंड शुरू हुआ है, ताकि पुलिस की नजरों से बचा जा सके।

भाग 2: न्याय का 'फास्ट ट्रैक'—14 माह, 320 को सजा

खबर का सबसे दमदार पहलू छत्तीसगढ़ की अदालतों का सख्त रुख है। रायपुर की नारकोटिक्स कोर्ट ने पिछले 14 महीनों में जो रफ्तार दिखाई है, वह देश के लिए एक नजीर है।

सजा के कड़े आंकड़े: तस्करों में खौफ

विशेष न्यायाधीशों की अदालतों में 2021 से 2025 तक के मामलों की सुनवाई पूरी कर ली गई है।

20 साल का कठोर कारावास: अजहरुद्दीन कुरैशी और नरेश निहाल जैसे सरगनाओं को न केवल 20 साल की जेल हुई, बल्कि भारी अर्थदंड भी लगाया गया।

सजा की झड़ी: पिछले 14 महीनों में 320 से अधिक तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा गया है।

वर्ष 2026 की शुरुआत: केवल शुरुआती तीन महीनों में ही 51 तस्करों को सजा सुनाई जा चुकी है, जिनमें 20, 15 और 10 साल की सजा वाले गंभीर मामले शामिल हैं।

"गवाहों का मुकरना अब मुश्किल है। पुलिस और अभियोजन की डे-टू-डे मॉनिटरिंग और साइंटिफिक रिपोर्ट्स के कारण अब आरोपी साक्ष्यों के अभाव में बच नहीं पा रहे हैं।" — **न्यायिक विश्लेषण**

भाग 3: विधानसभा में गूंजी 'नशे की दस्तक'

यह मामला सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है, बल्कि सदन में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में बीजेपी विधायकों ने नशे के बढ़ते जाल पर गहरी चिंता व्यक्त की।

नशेड़ियों की फौज: प्रदेश में गांजा पीने वालों की संख्या 3.50 लाख से बढ़कर 4 लाख हो गई है।

खतरे में बचपन: कफ सिरप और प्रतिबंधित गोलियों का शिकार होने वाले किशोरों की संख्या 40 हजार को पार कर गई है।

संपत्ति की कुर्की: सरकार ने तस्करी से कमाई गई ₹13.29 करोड़ से अधिक की संपत्ति को जब्त या फ्रीज करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।

भाग 4: 'ऑपरेशन निश्चय' और पुलिस का नया चक्रव्यूह

पुलिस ने अब रक्षात्मक के बजाय आक्रामक रणनीति अपनाई है। 'ऑपरेशन निश्चय' और 'ऑपरेशन प्रहार' के तहत छत्तीसगढ़ पुलिस के 'सिंघम' सड़कों पर उतरे हैं।

नोडल एजेंसी: रायपुर में एसीपी कोतवाली को तस्करी की रोकथाम के लिए नोडल बनाया गया है।

जमानत पर निगरानी

जेल से छूटने वाले तस्करों की हर हरकत पर पुलिस की पैनी नजर है ताकि वे दोबारा नेटवर्क न खड़ा कर सकें।

बड़ी कार्रवाई

पिछले तीन महीनों में अकेले महासमुंद पुलिस ने 5,629 किलोग्राम से अधिक गांजा जब्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

जस्टिस का ग्राफ (वर्ष 2026 के प्रथम 3 माह):

20 साल की सजा	:	02 मामले
15 साल की सजा	:	13 मामले
10 साल की सजा	:	08 मामले
5 साल से अधिक	:	12 मामले

'हब' और 'हथौड़े' के बीच पिसता नार्को-सिंडिकेट

छत्तीसगढ़ आज एक निर्णायक मोड़ पर खड़ा है। भौगोलिक रूप से सात राज्यों की सीमाओं को छूने वाला हमारा प्रदेश, नशे के सौदागरों के लिए 'प्रवेश द्वार' भी है और उनकी सबसे बड़ी 'चुनौती' भी। हालिया आंकड़े और अदालती फैसले यह स्पष्ट करते हैं कि राज्य अब नशे के खिलाफ सिर्फ कागजी जंग नहीं लड़ रहा, बल्कि उसने सीधे तस्करों की 'अर्थव्यवस्था' और 'आजादी' पर प्रहार करना शुरू कर दिया है।

एक गंभीर सामाजिक चेतावनी

संपादकीय चिंता का सबसे बड़ा विषय यह है कि छत्तीसगढ़ केवल एक 'रास्ता' (Transit Route) नहीं रह गया है, बल्कि धीरे-धीरे एक 'बाजार' में तब्दील हो रहा है। विधानसभा में पेश किए गए आंकड़े—4 लाख नशेड़ी और 40 हजार से अधिक किशोरों का नशे की गिरफ्त में होना—किसी भी सभ्य समाज के लिए खतरे की घंटी है। जब नशा गलियों तक पहुंचता है, तो वह केवल एक पीढ़ी को नहीं, बल्कि राज्य के भविष्य और उसकी कार्यक्षमता को नष्ट कर देता है।

पुलिस की सक्रियता और कोर्ट का 'कवच'

अक्सर देखा जाता है कि पुलिस तस्करों को पकड़ती तो है, लेकिन लचर पैरवी और गवाहों के मुकर जाने से वे सलाखों से बाहर आ जाते हैं। लेकिन रायपुर नारकोटिक्स कोर्ट के ताजा रुझान एक नई उम्मीद जगाते हैं। 14 माह में 320 से अधिक तस्करों को सजा सुनाना यह साबित करता है कि अब पुलिस की जांच और न्यायपालिका के बीच एक 'अदृश्य तालमेल' काम कर रहा है। 20-20 साल की कठोर सजा और करोड़ों की संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई यह संदेश है कि छत्तीसगढ़ की धरती अब तस्करी के लिए 'सॉफ्ट टारगेट' नहीं रही।

सिर्फ जब्ती काफी नहीं, 'जड़' पर प्रहार जरूरी

तस्करी के बदलते तौर-तरीकों (सोशल मीडिया और कूरियर का उपयोग) ने यह साफ कर दिया है कि यह लड़ाई अब केवल हाईवे पर नाकाबंदी तक सीमित नहीं रह सकती। हमें 'साइबर-इंटेलिजेंस' और 'सोशल-अवेयरनेस' के मोर्चे पर और अधिक आक्रामक होना होगा। पुलिस को 'ऑपरेशन निश्चय' को हाईवे से निकालकर उन मोहल्लों और शिक्षण संस्थानों तक ले जाना होगा जहां 'सूखे नशे' की छोटी खेपें पहुंच रही हैं।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक श्री सुकांत राजपूत द्वारा ए.आर. प्रिंटर्स, निरंकारी फर्नीचर के पीछे, पंडरी रायपुर से मुद्रित एवं शहरसत्ता, एस-15 प्रियदर्शिनी नगर, सेक्टर 1, मातृ-पितृ छाया अपार्टमेंट, रायपुर (छ.ग.),
मोबाईल नं. 98271-81979, फोन नं. 0771-3158142, संपादक - सुकांत राजपूत (पीआरबी एक्ट के तहत समाचार के लिए जिम्मेदार), महाप्रबंधक - प्रदीप चंद्रवंशी (मो. 70006-81023)। डाक पंजीयन - CG/RYP/DN/70/2025-27